RNI No. MPHIN/2015/64451 डाक पंजीयन क्र. MP/IDC/1525/2019-2021 IPT डाक द्वारा प्रेषण प्रति शुक्रवार indianplasttimes@gmail.com
www.Indianplasttimes.in

इंडियन प्लास्ट टाइम्स

■ INDORE ■ 01 JULY TO 07 JULY 2020 ■ प्रति बुधवार ■ वर्ष 05 ■ अंक 45 ■ पृष्ठ 8 ■ कीमत 5 रु.

Inside News

तेल विपणन कंपनियों को अबतक 92.5 करोड़ लीटर एथेनॉल की आपूर्ति: इसमा
Page 2

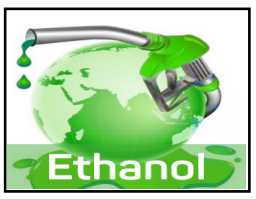

कोरोना काल में पहली बार आया जीएसटी डेटा जून में बढ़ा कलेक्शन
Page 3

शुरुआत और समापन में सावन शुभ, लेकिन कावड यात्रा नहीं निकलेगी
Page 6

editoria!

दरिद्र नारायण की सुधि

कोरोना, बारिश और त्योहारों के समय गरीब वर्ग को अन्न से संबल देने का प्रयास सराहनीय और स्वागतयोग्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ताजा घोषणा मूल रूप से देश के दरिद्र नारायण की सुधि लेने की ऐसी कोशिश है, जिसकी उम्मीद पिछले एक महीने से बंधी हुई थी। सरकार ने जुलाई से नवंबर तक पूरे पांच महीने तक देश के करीब 80 करोड़ जरूरतमंदों को पांच-पांच किलो गेहूं या चावल और चना मुफ्त देने का जो फैसला किया है, उससे देश को एक मानवीय आधार मिलेगा। यह आधार पूरे गुजारे के लिए भले पर्याप्त न हो, लेकिन इससे अभावग्रस्त परिवारों का मनोबल बढेग़ा। इस राहत के उपरांत वे अपने थोडे.से प्रयास या रोजगार योजनाओं का लाभ उठाकर अपने दिन ठीक से गुजार सकेंगे। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के नवंबर तक विस्तार से अभावग्रस्त लोगों को अपने यथास्थान रहने की प्रेरणा भी मिलेगी। विशेष रूप से बिहार जैसे श्रमिक बहुल राज्य में छठ पूजा का बहुत महत्व है, जिसे प्रधानमंत्री ने भी जाहिर किया है। बड़ी संख्या में ऐसे कामगार होंगे, जो अब नवंबर में छठ पूजा के समापन के बाद ही यात्रा की योजना बनाएंगे। बेशक, देखने वाले इस घोषणा को चुनाव से जोड़कर भी देखेंगे, लेकिन वह भी इस योजना के व्यापक महत्व से इनकार नहीं कर पाएंगे। एक और अच्छी बात है कि इस योजना का श्रेय किसानों और ईमानदार करदाताओं को दिया गया है। जब देश में कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है, तब सरकार का लोक-कल्याणकारी स्वरूप सशक्त होना ही चाहिए। इस योजना के विस्तार पर अगर 90 हजार करोड़ रुपये से अधिक खर्च होंगे, तो कोई बात नहीं। इस देश में ऐसी क्षमता है कि वह गरीबों के साथ खड़ा हो सकता है। यदि कोरोना के समय अमेरिका की कुल जनसंख्या से तीन गुना अधिक लोगों को हमारी सरकारों ने मुफ्त अनाज दिया है, तो कोई आश्चर्य नहीं। बहरहाल, यह भी जरूरी है कि ऐसी उदार योजनाओं का लाभ पूरी ईमानदारी से जरूरतमंदों तक पहुंचे। निचले स्तर पर वितरण से जुड़े लोगों के लिए भी यह परीक्षा और दरिद्र नारायण की सच्ची सेवा का समय है। अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि किसी बहाने से किसी भी जरूरतमंद को योजनाओं के लाभ से वंचित न किया जाए। प्रधानमंत्री के भाषण में एक और महत्वपूर्ण बात शामिल है, जो सबका ध्यान खींच रही है। 'एक देश एक राशन कार्ड' की घोषणा वैसे तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मई महीने के मध्य में ही कर दी थी और उन्होंने यह भी बता दिया था कि ऐसा मार्च 2021 में संभव हो जाएगा, लेकिन प्रधानमंत्री के बोलने से लोगों की उम्मीदें और बढ़ गई हैं। एक देश एक राशन कार्ड लंबे समय से इस देश की जरूरत रही है। सभी राज्य अगर इस व्यवस्था को मिलकर पहले ही साकार कर लेते, तो संभव है, कोरोना के समय लाखों की संख्या में लोगों को अपने घर न लौटना पड़ता। जो जहां है, वहीं रहता और वहीं उसे राशन कार्ड के तहत जरूरी सामान और अनाज उपलब्ध करा दिया जाता। अब समय आ गया है कि एक देश एक राशन कार्ड और मुफ्त अनाज जैसे बुनियादी इंतजामों को स्थानीय सियासत से परे रखकर मदद का स्थाई ढांचा विकसित किया जाए। ऐसी मदद की व्यवस्था जितनी उदार और व्यापक बनेगी, हमारा देश उतनी ही राहत और खुशी महसूस करेगा।

जल्द मजबूत होगा रुपया

भारतीय मुद्रा में 1 रुपये की मजबूती आने से तेल कंपनियों को 8000 करोड़ का सालाना लाभ

नई दिल्ली। एजेंसी

कोरोना संकट के दौर में पिछले कुछ माह में डॉलर के मुकाबले रुपये ने भारी दबाव झेला है। इस माह की शुरुआत में एक डॉलर की कीमत 76.91 रुपये प्रति डॉलर तक पहुंच गई थी। लेकिन विदेशी निवेश के प्रवाह और सस्ते कच्चे तेल की वजह से यह 76 रुपये प्रति डॉलर के स्तर से नीचे आ गया है। रिपोर्ट के मुताबिक सबकुछ सही रहा तो इस साल के अंत तक रुपया 72 के स्तर पर मजबूत हो सकता है। इसका सीधा फायदा उपभोक्ताओं को मिलेगा।

सोमवार को रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले सात पैसे बढ़कर 75.58 रुपये प्रति डॉलर पर बंद हुआ। इस साल की शुरुआत से अब तक रुपया पांच फीसदी टूट चुका है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक मौजूदा स्थिति में रुपया साल के अंत तक 75 रुपये प्रति डॉलर के स्तर जा सकता है। लेकिन हालात इसी तरह सुधरते रहे तो भारतीय मुद्रा में पांच फीसदी की तेजी साल के अंत तक पांच फीसदी तेजी के साथ 72 रुपये के स्तर पर भी पहुंच सकता है। जानकारों का कहना है कि सरकार के साथ उपभोक्ताओं, कंपनियों और निवेशकों को भी मजबूत रुपये का लाभ मिलेगा।

रुपये के मजबूत होने के फायदे

कच्चा तेल पर असर : इस क्षेत्र को रुपए की मजबूती से राहत मिलेगी, क्योंकि यह आयात किया जाता है। कच्चे तेल का आयात बिल में कमी आएगी और विदेशी मुद्रा कम खर्च करना होगा।

कैपिटल गुड्स: रुपए की मजबूती से इस सेक्टर को भी राहत मिलेगी, क्योंकि रुपए की मजबूती से भारत में सस्ते कैपिटल गुड्स मिलेंगे।

इलेक्ट्रॉनिक सामान : रुपया मजबूत हो तो इस क्षेत्र को भी लाभ हासिल होगा, क्योंकि सस्ते इलेक्ट्रॉनिक गुड्स आयात किए जा सकेंगे।

जेम्स एंड ज्वैलरी: रुपए की मजबूती का सकारात्मक असर इस सेक्टर पर दिखाई देगा। इससे यह सस्ता होगा और आयात पर भी इसका असर आएगा।

फर्टिलाइजर्स एंड कैमिकल्स : रुपए की मजबूती से यह भी सस्ता होगा। आयात करने वालों को यह कम रुपए में ज्यादा मिलेगा। तो रुपए की मजबूती इस सेक्टर को भी फायदा पहुंचाएगी।

रुपये के मजबूत होने के नुकसान

आईटी क्षेत्र को घाटा: अगर रुपया मजबूती के स्तर पर गया तो इस सेक्टर पर प्रतिकूल असर आएगा। कंपनियों को मिलने वाले काम पर आय कम होगी जिससे उनको नुकसान होगा।

दवा निर्यात: अगर रुपया मजबूत हुआ तो इस सेक्टर का निर्यात भी घटेगा।

हैंडीक्राफ्ट और टेक्सटाइल: अगर रुपया मजबूत हुआ तो इस सेक्टर को निर्यात में काफी नुकसान होगा। टेक्सटाइल निर्यात में भारत वैश्विक रैंकिंग में फिलहाल दो नंबर पर मौजूद है। यदि रुपया मजबूत हुआ तो इस सेक्टर को भी काफी नुकसान होगा।

पढ़ाई महंगी होगी: रुपया मजबूत होने से विदेशी में पढ़ाई करना महंगा हो जाएगा।

सेंसेक्स में 499 अंक की तेजी, निफ्टी 10,400 अंक के पार

मुंबई। एजेंसी

वैश्विक बाजारों से सकारात्मक संकेत मिलने के बीच बंबई शेयर बाजार में बुधवार को संवेदी सूचकांक 499 अंक की जोरदार छलांग के साथ 35,414.45 अंक पर बंद हुआ। इस दौरान सेंसेक्स में बड़े भारांक वाली कंपनियों एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी, रिलायंस इंडस्ट्रीज और आईटीसी में अच्छी बढ़त दर्ज की गई। कारोबार के दौरान बंबई शेयर बाजार का सूचकांक 35,467.23 अंक की ऊंचाई छूने के बाद अंत में 498.65 अंक यानी 1.43 प्रतिशत बढ़कर 35,414.45 अंक और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 127.95 अंक यानी 1.24 प्रतिशत बढ़कर 10,430.05 अंक पर पहुंचकर बंद हुआ। सेंसेक्स में शामिल में एक्सिस बैंक 6 प्रतिशत की बढ़ते के साथ सबसे अधिक लाभ में रहा।बजाज फिनसर्व, एचडीएफसी, बजाजा फाइनेंस, आईटीसी, इंडसइंड बैंक, स्टेट बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों में भी अच्छी बढ़त रही। दूसरे तरफ एनटीपीसी, नेस्ले इंडिया, लार्सन एण्ड टुब्रो, महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा और ओएनजीसी के शेयरों में गिरावट रही। **(शेष पृष्ठ 2 पर)**

मजबूत मांग से कच्चा तेल वायदा कीमतों में तेजी

नयी दिल्ली। एजेंसी

मजबूत हाजिर मांग के कारण कारोबारियों ने अपने सौदों के आकार को बढ़ाया जिससे वायदा कारोबार में बुधवार को कच्चातेल की कीमत 28 रुपये की तेजी के साथ 3,043 रुपये प्रति बैरल हो गई। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में कच्चातेल के जुलाई माह में डिलीवरी वाले अनुबंध की कीमत 28 रुपये अथवा 0.93 प्रतिशत की तेजी के साथ 3,043 रुपये प्रति बैरल हो गई जिसमें 3,415 लॉट के लिए कारोबार हुआ। बाजार विश्लेषकों ने कहा कि कारोबारियों द्वारा अपने सौदों के आकार को बढ़ाने के कारण यहां वायदा कारोबार में कच्चातेल वायदा कीमतों में तेजी आई। वैश्विक स्तर पर न्यूयॉर्क में वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट कच्चातेल की कीमत 2.37 प्रतिशत की तेजी के साथ 40.20 डॉलर प्रति बैरल हो गई, जबकि ब्रेंट क्रूड की कीमत 2.28 प्रतिशत की तेजी के साथ 42.21 डॉलर प्रति बैरल हो गई।

News यू केन USE

शेल ने अपनी तेल एवं गैस संपत्तियों का मूल्य 22 अरब डालर घटाया

लंदन। एजेंसी

ऊर्जा क्षेत्र की कंपनी रॉयल ढच शेल ने मंगलवार को आगाह किया कि वह कोविड- 19 महामारी के चलते तेल एवं गैस के दाम घटने कारण परिसंपत्तियों के मूल्यांकन क 22 अरब डालर की कमी कर सकती है। कंपनी ने तिमाही के दौरान संपत्तियों पर बट्टा लगने की घोषणा करते हुये कहा कि वह इस नीति पर चलती रहेगी कि चुनौतीपूर्ण समय में कारोबार में लचीलापन बना रहे। इस महीने की शुरुआत में शेल की प्रतिस्पर्धी कंपनी बीपी ने भी अपनी बही में संपत्ति का मूल्य 17.5 अरब डालर तक घटा दिया था। शेल ने अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रमुख तेल ब्रेंट क्रूड का भाव 2022 में 50 डालर प्रति बैरल रहने का अनुमान व्यक्ति किया है। इससे पहले कंपनी ने 60 डालर प्रति बैरल का भाव रहने का अनुमान लगाया था। मंगलवार को इस तेल का भाव 41 डालर प्रति बैरल के आसपास रहा।

बीपी ने पेट्रो रसायन कारोबार इकाई इनिओस को 5 अरब डॉलर में बेची

लंदन। एजेंसी

तेल एवं गैस कंपनी बीपी ने अपना वैश्विक पेट्रोरसायन कारोबार 5 अरब डॉलर में इनिओस को बेच दी है। ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों की ओर अपनी गतिविधियां बढ़ाने की योजना के तहत कंपनी ने यह कदम उठाया है। कंपनी ने सोमवार को एक बयान में यह जानकारी दी। बीपी के सीईओ बर्नार्ड लूने ने कहा कि यह सौदा कंपनी को प्रतिस्पर्धी बनाये रखने ऊर्जा क्षेत्र में बदलाव के जरिये सफल होने के प्रयास को प्रतिबिंबित करता है। बयान के अनुसार इससे प्राप्त राशि का उपयोग कंपनी की देनदारियां कम करने में किया जाएगा। कंपनी ने अपने कुछ काम धंधे बेच कर एक निश्चित धनराशि जुटाने की योजना निर्धारित समय से एक साल पहले पूरी कर ली है। कुल 5 अरब डॉलर का यह सौदा नियामकीय और अन्य मंजूरी पर निर्भर है। सौदा 2020 के अंत तक पूरा होने की उम्मीद है।

विदेशी मुद्रा भंडार में वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान 64.9 अरब डॉलर की बढ़ोतरी

मुंबई। एजेंसी

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के मुताबिक देश के विदेशी मुद्रा भंडार में वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान 64.9 अरब डॉलर की बढोतरी हुई, जबकि इसमें वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान 11.7 अरब डॉलर की कमी हुई थी। भारतीय रिजर्व बैंक ने एक विज्ञप्ति में कहा कि भंडार में हुई इस वृद्धि में मूल्यांकन प्रभाव समायोजित हैं। विज्ञप्ति में कहा गया कि भुगतान संतुलन के आधार पर (मूल्यांकन प्रभाव को छोड़कर) विदेशी मुद्रा भंडार में वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान 59.5 अरब डॉलर की बढ़ोतरी हुई, जबकि वित्त वर्ष 2018-19 में इसमें 3.3 अरब डॉलर की गिरावट हुई थी।

सेंसेक्स में 499 अंक की तेजी

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

कारोबारियों के मुताबिक स्टाक से जुड़ी खास गतिविधि के अलावा वैश्विक बाजारों का भी सूचकांक पर असर रहा। वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में सुधार के संकेत से वृहद आर्थिक परिवेश सकारात्मक हुआ है और इसका दुनिया के शेयर बाजारों में अच्छा असर दिखा। एशिया में शंघाई और हांग कांग के बाजार बढ़त के साथ बंद हुये जबकि टोक्यो और सोल में गिरावट आयी । यूरोप के शेयर बाजारों में कारोबार की शुरुआत सकारात्मक रही। अंतरराष्ट्रीय बाजार में बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड तेल का वायदा भाव 2.67 प्रतिशत बढ़कर 42.37 डालर प्रति बैरल पर पहुंच गया। अमेरिकी डालर के मुकाबले रुपया 9 पैसे गिरकर प्रति डालर 75.60 डालर पर बंद हुआ।

तेल विपणन कंपनियों को अबतक 92.5 करोड़ लीटर एथेनॉल की आपूर्तिः इसमा

नयी दिल्ली। एजेंसी

चीनी मिलों ने नवंबर को समाप्त आपूर्ति वर्ष में तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) को 170 करोड़ लीटर एथेनॉल की आपूर्ति के लिये अनुबंध किया जो पिछले साल की तुलना में कम है। उद्योग के आंकड़े के अनुसार पेट्रोल में मिश्रण के लिये इसमें से अबतक 92.5 करोड़ लीटर की आपूर्ति की गयी है। तेल विपणन कंपनियां पेट्रोल में 5 प्रतिशत से अधिक एथेनॉल के मिश्रण में कामयाब हुई हैं। इससे पूर्व एथेनॉल आपूर्ति वर्ष 2018-19 (दिसंबर-नवंबर) के दौरान 190 लीटर की आपूर्ति की गयी थी।

भारतीय चीनी मिलों के संघ (इसमा) ने एक बयान में कहा, ''एथेनॉल विनिर्माताओं और ओएमसी के बीच मौजूदा एथेनॉल आपूर्ति वर्ष 2019-20 के लिये 170 करोड़ लीटर की आपूर्ति को लेकर अनुबंध हुआ है।'' संघ ने कहा कि एक दिसंबर 2019 से 22 जून 2020 के दौरान तेल विपणन कंपनियों को 92.5 करोड़ लीटर एथेनॉल की आपूर्ति की गयी। इससे पेट्रोल में अखिल भारतीय स्तर पर औसतन 5.09 प्रतिशत प्रतिशत एथेनॉल का मिश्रण हुआ है। उत्तर प्रदेश, हरियाण, पंजाब, उत्तराखंड, बिहार और कर्नाटक समेत कुछ राज्यों में पेट्रोल में एथेनॉल का मिश्रण 8.5 से 9.8 प्रतिशत तक है।

इसमा ने कहा कि बी श्रेणी के शीरा और गन्ने के रस से तैयार 58 करोड़ लीटर एथेनॉल की आपूर्ति तेल विपणन कंपनियों को की गयी है। अनुबंध के तहत 23 करोड़ लीटर एथेनॉल 30 नवंबर, 2020 तक आपूर्ति की जाएगी। इसमा के अनुसार बी-शीरा और गन्ने के रस से चीनी के बजाए एथेनॉल तैयार होने से करीब 8 लाख टन चीनी उत्पादन पर असर पड़ा है। संगठन के अनुसार इससे न केवल देश में अधिशेष चीनी कम होगी बल्कि चीनी मिलों के लिये उसी अनुपात में माल रखरखाव की लागत कम होगी।

इसमा ने कहा कि इससे मिलों को बेहतर रिटर्न भी मिलेगा क्योंकि सरकार द्वारा तय एथेनॉल का मूल्य चीनी की तुलना में ज्यादा लाभकारी है। संगठन ने कहा कि इस विपणन वर्ष में एथेनॉल की आपूर्ति कम होने का कारण महाराष्ट्र और कर्नाटक समेत दक्षिण के कुछ राज्यों में सूखा पड़ना है। इससे गन्ने और चीनी के उत्पादन पर असर पड़ा है। अच्छी बारिश और पानी की उपलब्धता से 2020-21 में गन्ने का रकबा सामान्य होने और गन्ने के उत्पादन में सुधार की उम्मीद है। इसीलिए सरकार ने 2020-21 में एथेनॉल उत्पादन और आपूर्ति 300 से 350 करोड़ लीटर रहने का लक्ष्य रखा है। साथ ही पेट्रोल में 7.5 से 8 प्रतिशत एथेनॉल मिश्रण का स्तर हासिल करने का लक्ष्य तय किया है। सरकार ने राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति, 2018 के अनुसार पेट्रोल में एथेनॉल मिश्रण के लिये 2022 तक 10 प्रतिशत और 2030 तक 20 प्रतिशत का लक्ष्य रखा है।

कोयला, बिजली सहित 23.4 फीसदी घटा 8 मुख्य इंडस्ट्रीज का उत्पादन

नयी दिल्ली। एजेंसी

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार कोरोवायरस के कारण लगाए गए लॉकडाउन के चलते मई में आठ मुख्य इंफ्रास्ट्रक्चर उद्योगों के उत्पादन में 23.4 प्रतिशत की भारी गिरावट आई। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा मंगलवार को जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार मई 2019 में इन 8 मुख्य क्षेत्रों के उत्पादन में 3.8 फीसदी की बढ़ोतरी हुई थी। उर्वरक को छोड़कर बाकी सभी सात क्षेत्रों, जिनमें कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, इस्पात, सीमेंट और बिजली शामिल हैं, में मई में नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई।

अप्रैल-मई में कैसा रहा प्रदर्शन

पिछले वित्त वर्ष में अप्रैल-मई में इन 8 मुख्य क्षेत्रों के उत्पादन में 4.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई थी, मगर वित्त वर्ष 2020-21 की समान अवधि में इन क्षेत्रों का उत्पादन 30 प्रतिशत घटा है। मंत्रालय की तरफ से बयान में कहा गया है कि अप्रैल और मई 2020 के दौरान कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन के मद्देनजर विभिन्न उद्योगों (कोयला, सीमेंट, स्टील, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी, क्रूड ऑयल आदि) के उत्पादन में काफी नुकसान हुआ है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) में इन आठ उद्योगों का योगदान 40.27 प्रतिशत रहता है।

आईआईपी में भारी गिरावट

आईआईपी के आंकड़े पिछले महीने अप्रैल के लिए सरकार की तरफ से जारी किए गए थे, जिनमें इसमें भारी गिरावट की बात सामने आई थी। लॉकडाउन के चलते भारत के आईआईपी में अप्रैल में कम से कम दो दशकों की सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गयी। औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक अप्रैल में सालाना 55.5 फीसदी घट गया, जो 1996 के बाद से सबसे बड़ी गिरावट है। इसकी मार्च के संशोधित 18.3 फीसदी गिरावट के साथ तुलना की गई है। 25 मार्च से लॉकडाउन लागू होने के बाद अधिकांश औद्योगिक क्षेत्र ठप्प पड़े हैं। हालांकि कहा गया था कि बाद में जारी किए जाने वाले संशोधित होंगे जिनमें थोड़े सुधार की संभावना है।

एक माह में तीसरी बार महंगा हुआ विमान ईंधन

नई दिल्ली। एजेंसी

जुलाई के पहले ही दिन विमान ईंधन एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) की कीमतों में वृद्धि की गई है। इसमें 7.5 फीसदी की बढ़ोतरी हुई, जबकि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज लगातार दूसरे दिन कोई बदलाव नहीं हुआ। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों के अनुसार दिल्ली में विमान ईंधन की कीमत 2,922.94 रुपये प्रति किलो लीटर (केएल) या 7.48 फीसदी बढ़कर 41,992.81 रुपये प्रति किलो लीटर हो गई है।

एक माह में तीसरी बार हुई वृद्धि

मालूम हो कि एटीएफ की कीमत में एक महीने में यह तीसरी वृद्धि है। इससे पहले एक जून को 56.6 फीसदी (12,126.75 रुपये प्रति किलो लीटर) की बढ़ोतरी हुई थी, जबकि 16 जून को 16.3 फीसदी (5,494.5 रुपये प्रति किलो लीटर) की बढ़ोतरी हुई।

पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं

दूसरी ओर देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार दूसरे दिन कोई बदलाव नहीं हुआ है। इससे पहले डीजल की कीमत में तीन हफ्तों के दौरान 22 बार बढ़ोतरी की गई थी, जिसके बाद डीजल रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया।

प्रमुख महानगरों में इतनी है कीमत

दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 80.43 रुपये प्रति लीटर है। वहीं, डीजल की कीमत 80.53 रुपये प्रति लीटर है। आईओसीएल की वेबसाइट से मिली जानकारी के अनुसार, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में एक लीटर पेट्रोल की कीमत क्रमशः 82.10, 87.19 और 83.63 रुपये प्रति लीटर है। डीजल की बात करें, तो इन महानगरों में इसका दाम क्रमशः 75.64, 78.83 और 77.72 रुपये है। पेट्रोल-डीजल की कीमतों को लेकर कांग्रेस द्वारा देशव्यापी विरोध किया गया था। अंतरराष्ट्रीय बाजार में इस महीने के अधिकतर दिन कच्चे तेल की कीमतों में नरमी का रुख रहा, लेकिन घरेलू बाजार में पेट्रोल-डीजल की कीमतें लगातार बढ़ी हैं। पिछले 24 दिनों में डीजल की कीमत में 11.23 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। इतने दिनों में पेट्रोल का दाम भी 9.17 रुपये प्रति लीटर चढ़ गया।

जीएसटी की तीसरी वर्षगांठ

जानें क्या हैं इसके मकसद और फायदे

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

देश में वस्तु एवं सेवा कर को लागू हुए तीन साल पूरे हो गए हैं। नरेंद्र मोदी सरकार ने ऐतिहासिक टैक्स सुधार की दिशा में एक जुलाई 2017 को अप्रत्यक्ष कर की इस नई व्यवस्था को लागू किया था, जो टैक्स के मोर्चे पर सुधार का बड़ा कदम था। इसकी शुरुआत के दौरान जीएसटी को बहुत आलोचना का सामना करना पड़ा था। हालांकि, आम आदमी को समय के साथ-साथ इसके लाभों का एहसास हुआ है।

इधर यह जानना जरूरी है कि जीएसटी एक ऐसा कर है जो खरीदार सरकार को सीधे भुगतान नहीं करते हैं। वे इसे विक्रेताओं को भुगतान करते हैं और ये निर्माता और विक्रेता तब सरकार को इसका भुगतान करते हैं।

जीएसटी का सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि उपभोक्ता देश में कहीं भी एक ही कीमत पर उत्पाद का लाभ उठा सकता है। हालांकि, GST टैक्स-स्लैब के तहत आने वाले उत्पाद इस लाभ के अंतर्गत आते हैं। प्रमुख लाभों में से एक पारदर्शिता भी है, जो जीएसटी के साथ आती है। यह व्यापारियों के लिए व्यापार लेनदेन को आसान बनाता है क्योंकि उन्हें आपूर्ति श्रृंखला के साथ खरीदे गए सभी चीजों के लिए जीएसटी का भुगतान करना पड़ता है।

जीएसटी लागू करने के पांच मकसद

■महंगाई पर लगाम ■अनुपालन बोझ कम करना ■टैक्स चोरी पर लगाम ■GDP में इजाफा ■टैक्स कलेक्शन बढ़ाना

जीएसटी के बाद देश में टैक्स फाइल करने वालों की संख्या में इजाफा हुआ है। करोड़ों नए कारोबारियों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। हालांकि सरकार के टैक्स कलेक्शन में ज्यादा इजाफा नहीं हुआ है। जब जीएसटी लागू हुआ था तो उम्मीद की गई थी कि प्रति महीने 1.5 लाख करोड़ रुपये का जीएसटी कलेक्शन होगा। कोशिशों के बावजूद कलेक्शन एक लाख करोड़ रुपये के आसपास ही रहा है।

जीएसटी के आने से कारोबारियों को अपना टैक्स रिटर्न डिजिटल तरीके से भरना होता है और ग्राहकों को दिए गए बिल में जीएसटी का विवरण देना होता है। इससे फायदा य हुआ कि कारोबारियों द्वारा की जा रही टैक्स चोरी पर लगाम लगाया है।

जून में 90,917 करोड़ रुपये रहा जीएसटी संग्रह

सरकार ने जून में जीएसटी से 90,917 करोड़ रुपये एकत्र किए। ये आंकड़ा मई में 62,009 करोड़ रुपये और अप्रैल में 32,294 करोड़ रुपये था। एक आधिकारिक बयान के मुताबिक, 'जून, 2020 में एकत्र सकल जीएसटी राजस्व 90,917 करोड़ रुपये है, जिसमें सीजीएसटी 18,980 करोड़ रुपये, एसजीएसटी 23,970 करोड़ रुपये, आईजीएसटी 40,302 करोड़ रुपये (माल के आयात पर जमा किए गए 15,709 करोड़ रुपये सहित) और उपकर 7,665 करोड़ रुपये हैं।' सरकार ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा में राहत दी है। जून 2020 के दौरान अप्रैल, मार्च और यहां तक कि फरवरी के रिटर्न भी दाखिल किए गए।

कोरोना काल में पहली बार आया जीएसटी डेटा जून में बढ़ा कलेक्शन

नई दिल्ली। एजेंसी।

देश में लॉकडाउन में ढील के बाद आर्थिक गतिविधियों के जोर पकड़ने से जीएसटी संग्रह (GST collection) में भी तेजी आई है। जून में जीएसटी संग्रह 90917 करोड़ रुपये रहा। हालांकि यह पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 91 फीसदी है लेकिन इस साल अप्रैल और मई के मुकाबले इसमें काफी बढ़ोतरी हुई है। अप्रैल में जीएसटी कलेक्शन 32294 करोड़ रुपये और मई में 62009 करोड़ रुपये रहा था। साल की पहली तिमाही में जीएसटी कलेक्शन पिछले साल की तुलना में 59 फीसदी रहा है। कोरोना काल में पहली बार जीएसटी का डेटा आया है। इससे पहले जारी नहीं हो रहा था।

सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक जून में जीएसटी संग्रह 90917 करोड़ रुपये रहा। इसमें केंद्रीय जीएसटी 18980 करोड़ रुपये, राज्य जीएसटी 23970 करोड़ रुपये और एकीकृत जीएसटी 40302 करोड़ रुपये रहा। उपकर के रूप में सरकार को जून में 7665 करोड़ रुपये मिले। केंद्र सरकार ने रेगुलर सेटलमेंट के रूप में 13325 करोड़ रुपये सीजीएसटी और 11117 करोड़ रुपये एसजीएसटी के रूप में सेटल किए हैं। इस तरह इस सेटलमेंट के बाद केंद्र को राजस्व के रूप में जून में 32305 करोड़ रुपये और राज्यों को 35087 करोड़ रुपये मिले।

कोरोना से प्रभावित हुआ सरकार का राजस्व

जून का जीएसटी कलेक्शन पिछले साल इसी महीने की तुलना में 91 फीसदी है। हालांकि सरकार ने जीएसटी रिटर्न फाइल करने में छूट दी थी इसलिए फरवरी, मार्च और अप्रैल के कुछ रिटर्न जून में दाखिल किए गए। इसी तरह मई के कुछ रिटर्न जुलाई के पहले कुछ दिनों में दाखिल किए जाएंगे।

कोरोना महामारी के कारण इस वित्त वर्ष में सरकार का राजस्व बुरी तरह प्रभावित हुआ है। अप्रैल में जीएसटी कलेक्शन 32294 करोड़ रुपये रहा था जो पिछले साल की समान अवधि की तुलना में केवल 28 फीसदी था। इस साल मई में यह 62009 करोड़ रुपये रहा जो पिछले साल मई में आए कलेक्शन का 62 फीसदी था। हालांकि बड़ी संख्या में करदाताओं ने अपने मई के रिटर्न दाखिल नहीं किए हैं।

कम हुआ देश का चालू खाता घाटा

जनवरी-मार्च 2020 में बचे 60 करोड़ डॉलर

मुंबई। देश के चालू खाते में वित्त वर्ष 2019-20 की जनवरी-मार्च तिमाही में 60 करोड़ डॉलर की बचत (Savings) दर्ज की है। ये रकम देश के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के 0.1 फीसदी के बराबर है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बताया कि वित्त वर्ष 2018-19 की समान तिमाही में देश ने जीडीपी के 0.7 फीसदी या 4.6 अरब डॉलर का चालू खाते का घाटा दर्ज किया था। वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान चालू खाते का घाटा कम होकर जीडीपी का 0.9 फीसदी हो गया है।

मार्च तिमाही में व्यापार घाटा भी हुआ है कम

चालू खाते में वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान जीडीपी के 2.1 फीसदी के बराबर घाटा दर्ज किया गया था। मार्च 2020 तिमाही और पूरे वित्त वर्ष में चालू खाते की स्थिति में सुधार से व्यापार घाटा कम हुआ है। चालू खाता किसी अवधि में वस्तु व सेवा का आयात-निर्यात, विदेशी निवेशकों को किए गए भुगतान और उनकी ओर से देश में आए धन की शुद्ध स्थिति बताता है। यह शेष दुनिया के साथ देश के कारोबार की स्थिति का अहम संकेतक होता है। केंद्रीय बैंक ने कहा है कि मार्च तिमाही में चालू खाते में बचत की प्रमुख वजह व्यापार घाटा कम होना है।

विदेश में बसे भारतीयों ने भी जमकर भेजा पैसा

आरबीआई ने बताया कि मार्च तिमाही में व्यापार घाटा कम होकर 35 अरब डॉलर रहा। इसके अलावा शुद्ध अदृश्य प्राप्तियां भी 35.6 अरब डॉलर रहीं। मार्च तिमाही में सेवा व्यापार से शुद्ध राजस्व बढ़कर 22 अरब डॉलर पर पहुंच गया, जो एक साल पहले की समान अवधि में 21.3 अरब डॉलर था। रिजर्व बैंक ने कहा कि कंप्यूटर और यात्रा सेवाओं से शुद्ध आमदनी बढ़ने से इसमें इजाफा दर्ज किया गया है। इस दौरान विदेशों में काम करने वाले भारतीयों की ओर से भेजा जाने वाला धन 14.8 फीसदी बढ़कर 20.6 अरब डॉलर पर पहुंच गया।

शुद्ध विदेशी निवेश बढ़कर हुआ 12 अरब डॉलर

रिजर्व बैंक ने बताया कि इस दौरान प्राथमिक आय खाते से शुद्ध भुगतान घटकर 4.8 अरब डॉलर रह गया, जो इससे पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में 6.9 अरब डॉलर था। मार्च तिमाही में शुद्ध विदेशी निवेश (Net Foreign Investment) दोगुना होकर 12 अरब डॉलर पर पहुंच गया, जो एक साल पहले 6.4 अरब डॉलर था। विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (FPI) इस दौरान 13.7 अरब डॉलर घट गया, जबकि एक साल पहले समान अवधि में यह 9.4 अरब डॉलर बढ़ा था।

55,000 रुपये हो सकता है 10 ग्राम सोने का रेट

नई दिल्ली। एजेंसी

अंतरराष्ट्रीय बाजार में कारोबार के मंद पड़ने और कोरोना महामारी का अब तक कोई हल नहीं निकलने का असर सोने की कीमतों पर दिखने लगा है। सोने के दाम बुलियन मार्केट में 50,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के करीब कारोबार कर रहा है। लेकिन इससे भी अहम बात ये है कि आने वाले दिनों में प्रति 10 ग्राम सोने की कीमत 55,000 हजार रुपये तक पहुंच सकता है।

यहां जानिए सोने के महंगे होने की वजह

निवेशक सुरक्षित इनवेस्टमेंट (Safe investment) के तौर पर लगातार सोने में पैसा लगा रहे हैं। हांगकांग (Hong Kong) की स्थिति पर चीन (China) और अमेरिका (US) के रुख से भी सोने के दामों में तेजी आई है। बाजार के जानकारों के मुताबिक अमेरिका में लगातार बढ़ते COVID-19 मरीजों की संख्या और शेयर बाजार में गिरावट के चलते आने वाले दिनों में सोने में निवेश और बढ़ेगा। जानकारों के मुताबिक 2020 के अंत तक सोने के दाम 55000 रुपये प्रति 10 ग्राम तक जा सकते हैं।

India Bullion and Jewellers Association (IBJA) के राष्ट्रीय अध्यक्ष पृथ्वीराज कोठारी के मुताबिक सोने के दामों में इस लिए तेजी देखी जा रही है क्योंकि कोरोना वायरस के चलते शेयर बाजार में गिरावट देखी जा रही है। बड़े इनवेस्टर (Big investor) अपना ज्यादा से ज्यादा पैसा सोने में लगा रहे हैं। जानकारी के अनुसार कोरोना वायरस महामारी के (Corona virus epidemic) चलते पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं (economies) मुश्किल दौर से गुजर रही हैं। अमेरिका सहित कई देश बाजार में पैसे की कमी न हो इसके लिए नोट छाप रहे हैं। इसका असर भी सोने की कीमतों पर पड़ रहा है।

IBJA के राष्ट्रीय अध्यक्ष के मुताबिक फिलहाल सोना लगभग 50,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास कारोबार कर रहा है। लेकिन अगर जल्द ही कोरोना वायरस पर लगाम नहीं लगती है तो सोने के दाम 2020 के अंत तक 55000 रुपये प्रति 10 ग्राम तक जा सकते हैं। बताते चलें कि अंतरराष्ट्रीय कारणों से सोने के दामों में तेजी बनी हुई है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने के दाम लगातार 1,750 डॉलर प्रति आउंस के ऊपर बना हुआ है। वहीं अब हाजिर सोना 1,750 से 1,815 डॉलर प्रति आउंस के बीच कारोबार कर रहा है। हांगकांग (Hong Kong) पर चीन (China) और अमेरिका (US) के रुख के चलते आने वाले दिनों में सोने के दामों में और तेजी दिखेगी। सोने के दामों में जल्द ही वर्तमान स्तर से 1000 रुपये प्रति 10 ग्राम तक की तेजी देखी जा सकती है।

बड़े कॉरपोरेट घरानों को बैंक खोलने की छूट देने पर हो विचार : पूर्व डिप्टी गवर्नर

मुंबई। एजेंसी

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के पूर्व डिप्टी गवर्नर आर गांधी ने सोमवार को कहा कि केंद्रीय बैंक को उन नियमों पर पुनर्विचार करने की जरूरत है, जो बड़े कॉरपोरेट घरानों को बैंकों का प्रवर्तक बनने से रोकते हैं। उन्होंने कहा कि अवश्यक सुरक्षा उपायों के साथ बैंकों में किसी एक निकाय को हिस्सेदारी 26 प्रतिशत से ऊंचा करने की मंजूरी दी जानी चाहिये। उन्होंने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था की आवश्यकताएं व आकांक्षाएं इस प्रकार की है जिसको देखते हुए बैंकिंग क्षेत्र में बड़ी पूंजी के स्रोतों को प्रवेश देने पर विचार करने की जरूरत है।इससे बड़ी परियोजनाओं की मदद में आसानी हो सकती है। उन्होंने संपूर्ण सेवा बैंकिंग माडल पर फिर ध्यान देने की भी वकालत की। गांधी रिजर्व बैंक के अपने कार्यकाल में महत्वपूर्ण बैंकिंग विनियमन और पर्यवेक्षण कार्यों की जिम्मेदारी संभाला करते थे। उन्होंने कहा कि केंद्रीय बैंक ने बैंकिंग लाइसेंस के लिये आवेदन की निरंतर खुली व्यवस्था चार साल से चल रही है, लेकिन इसके बाद भी कोई गंभीर आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। गांधी की यह टिप्पणी ऐसे समय आयी है, जब रिजर्व बैंक ने निजी बैंक के स्वामित्व तथा नियंत्रण को लेकर इस महीने की शुरुआत में एक आंतरिक कार्य समूह का गठन किया है। यह समूह प्रवर्तकों की हिस्सेदारी, हिस्सेदारी कम करने की आवश्यकताएं, नियंत्रण और मतदान के अधिकार जैसे पहलुओं पर विचार करेगा। गांधी ने भुगतान कंपनी ईपीएस द्वारा आयोजिक एक सेमिनार में कहा, ''मेरे विचार में, स्पष्ट रूप से, एक प्रवर्तक या रणनीतिक निवेशक के लिये 26 प्रतिशत जैसी गंभीर हिस्सेदारी निश्चित रूप से बैंक और बैंकिंग उद्योग के दीर्घकालिक हित के लिये अच्छी होगी।'' कोटक महिंद्रा बैंक को दी गयी छूट का हवाला देते हुए, गांधी ने कहा कि रिजर्व बैंक ऐसे कदमों पर गौर कर सकता है। कोटक महिंद्रा बैंक के मामले में प्रवर्तक समूह को लंबी अवधि में 26 प्रतिशत हिस्सेदारी रखने की अनुमति दी गयी है, लेकिन उसके मतदान के अधिकार 15 प्रतिशत तक सीमित होंगे। उन्होंने स्वतंत्र निदेशकों की शक्तियों को बढ़ाने, निदेशक मंडल में प्रवर्तकों की सीटों को सीमित करने और निर्णय लेने को प्रभावित करने की उनकी क्षमता जैसे अन्य पहलुओं का भी सुझाव दिया। गांधी ने कहा, 'प्राथमिक समस्या, जो हमने राष्ट्रीयकरण से पहले भी देखी थी, वह है कि हितों का टकराव, निधियों का विभाजन, जमाकर्ताओं के बजाय समूहों के हित के आधार पर बैंक के निर्णय जैसी चीजें होती हैं।'' गांधी ने कहा कि अभी आरबीआई प्रवर्तक को 15 प्रतिशत और अन्य व्यक्तियों को 10 प्रतिशत तक हिस्सेदारी रखने की अनुमति देता है। संकटग्रस्त बैंकों के मामले में वह अधिक हिस्सेदारी की भी मंजूरी दे सकता है। पीएमसी सहकारी बैंक और यस बैंक जैसे मुद्दों पर एक सवाल के जवाब में गांधी ने कहा कि कंपनी संचालन को अधिक महत्व दिया जाना चाहिये। यह हमेशा स्वामित्व का स्तर ही नहीं है, जो परेशानी का कारण बन सकता है। उन्होंने कहा कि पेशेवर भी बाजार में अपने स्टैंड का लाभ उठा सकते हैं और बैंक स्थापित करने में मदद कर सकते हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि इसके अनुभव कुछ मामलों में सफल रहा है और कुछ मामलों में नहीं। उन्होंने छोटे बैंकों का आपस में विलय कर बड़े बैंक बनाने से जुड़े एक सवाल पर कहा कि भारत भौगोलिक दृष्टि से भी बहुत बड़ा देश है और विविधता के नजरिये से भी। अतः हमें हर आकार के बैंकों की जरूरत है, जो हर किसी की जरूरतों को पूरा कर सकें।

बीते वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में आवास मूल्य सूचकांक 3.9 प्रतिशत बढ़ा : रिजर्व बैंक

नयी दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

बीते वित्त वर्ष 2019-20 की चौथी तिमाही में आवास मूल्य सूचकांक एक साल पहले की समान अवधि की तुलना में 3.9 प्रतिशत बढ़ा। रिजर्व बैंक ने मंगलवार को यह जानकारी दी। हालांकि, इससे पिछली तिमाही की तुलना में इसमें 0.2 प्रतिशत की गिरावट आई । रिजर्व बैंक ने 2019-20 की चौथी तिमाही के लिए अपना तिमाही आवास मूल्य सूचकांक (एचपीआई) जारी किया है। एचपीआई की गणना 2010-11 के आधार वर्ष पर होती है।यह सूचकांक दस प्रमुख शहरों...अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, जयपुर, कानपुर, कोच्चि, कोलकाता, लखनऊ और मुंबई के आवास पंजीकरण प्राधिकरणों से मिले लेनदेन स्तर के आंकड़ों पर आधारित है। बयान में कहा गया है कि अखिल भारतीय एचपीआई तिमाही दर तिमाही आधार पर 0.2 प्रतिशत घट गया। इसकी मुख्य वजह दिल्ली, बेंगलुरु, अहमदाबाद और जयपुर में घरों की कीमतों में गिरावट है। तिमाही आधार पर मुंबई में घरों के दाम सबसे अधिक बढ़े। हालांकि, सालाना आधार पर अखिल भारतीय एचपीआई चौथी तिमाही में 3.9 प्रतिशत बढ़ गया।

एसबीआई ने तीन शहरों में खोली 'योनो' शाखाएं

मुंबई। आईपीटी नेटवर्क

भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने चुनिंदा शहरों में 'योनो शाखाएं' खोली हैं। इसका मकदस बैंक के ग्राहकों के बीच डिजिटल बैंकिंग अपनाने को बढ़ावा देना है। योनो (यू ओनली नीड वन) एसबीआई की डिजिटल बैंकिंग एप है। बैंक ने एक विज्ञप्ति ने कहा कि उसने पायलट परियोजना के तहत नवी मुंबई, इंदौर और गुरुग्राम में एक-एक योनो शाखा खोली है। एसबीआई के चेयरमैन रजनीश कुमार ने कहा, '' हमें भरोसा है कि योनो शाखा ग्राहकों को डिजिटल बैंकिंग अपनाने में सशक्त बनाएगी और इसकी मदद से वह आसानी से सभी बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठा पाएंगे।'' बैंक के स्व-सेवा केंद्रों पर ग्राहक चौबीसों घंटे स्मार्ट मशीनों से चेक जमा करने, पैसा निकालने, पैसा जमा करने और पासबुक प्रिंट करने का काम कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें बैंक के कर्मचारियों पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं होती। बैंक ने अपनी स्थापना की 65वीं वर्षगांठ पर इन शाखाओं को पेश किया। बैंक की योजना अगले पांच साल में देशभर में ऐसी शाखाएं खोलने की है।

वोकल फोर लोकल

सेल ने देश में ही बनाई रेल की लंबी पटरियां

यूरोप से लाने की नहीं होगी जरूरत

नई दिल्ली। नए भारत के निर्माण में अब रेलवे को गुणवत्तापूर्ण रेल पटरी भी यहीं मिलेगी। पहले, इस तरह की गुणवत्तापूर्ण रेल की पटरी के लिए विदेशों, खास कर यूरोपीय देशों की तरफ ताकना पड़ता था। अब स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (SAIL) ने इस तरह की रेल पटरी का निर्माण अपने भिलाई स्टील प्लांट में शुरू कर दिया है। इस तरह की पटरियों की पहली खेप कल, 30 जून 2020 को भिलाई से रवाना भी कर दी गई है।

सेल के निदेशक (परियोजना एवं व्यापार योजना) एवं सीईओ, भिलाई इस्पात संयंत्र (अतिरिक्त प्रभार) आनिर्बान दासगुप्ता के मुताबिक सेल ने रेलवे के लिए R260 ग्रेड के वैनेडियम अलॉयड स्पेशल ग्रेड प्राइम रेल का उत्पादन यहीं शुरू कर दिया है। इस तरह की रेल की पटरी पहले भारत में नहीं बनती थी, इसलिए गुणवत्तापूर्ण पटरी के लिए विदेशों, खास कर यूरोपीय देशों की तरफ ताकना पड़ता था। लेकिन अब सेल के भिलाई प्लांट जो R260 ग्रेड का रेल रोल किया गया है, वह यूरोपियन मानक से भी बेहतर है। यूरोपियन स्पेसिकेशन के 2.5 पीपीएम (अधिकतम) हाईड्रोजन कंटेन्ट की तुलना में भिलाई के रेल में 1.6 पीपीएम (अधिकतम) हाईड्रोजन कंटेन्ट है, जो कि यूरोपियन स्पेसिकेशन अधिक क्षमतावान है। इसे रेलवे के अनुसंधान संगठन आरडीएसओ की भी हरी झंडी मिल गई है।

रेलवे को अब इसी तरह की पटरी की जरूरत

भारतीय रेल अब अपनी गाड़ियों को तूफान की रफ्तार से चलाना चाहता है। साथ ही मालगाड़ियों में अब पहले से बहुत ज्यादा सामान ढोया जाता है। इसलिए इसे बेहतर गुणवत्ता वाली रेल की पटरी चाहिए। इसके लिए सेल ने ''260 ग्रेड विकसित करने के साथ ही सफलतापूर्वक उत्पादन शुरू कर दिया है। सेल भारतीय रेल को यह रेल 260 मीटर लंबे वेल्डेड पैनल के रूप में आपूर्ति कर रही है।

पहली खेप रवाना

इस गुणवत्तापूर्ण रेल की पहली खेप कल ही रवाना हुई है। इस अवसर पर रेलवे बोर्ड के सदस्य (इंजीनियरिंग) विश्वेश चौबे, इस्पात मंत्रालय की एडिशनल सेक्रेटरी रसिका चौबे और ज्वाइंट सेक्रेटरी पुनीत कंसल समेत सेल अध्यक्ष अनिल कुमार चौधरी एवं रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी आनलाइन तरीके से उपस्थित थे।

सेल है रेलवे की गति की आधारशिला

सेल भारतीय रेल की उस गति की आधारशिला है, जिस पर पूरा देश दौड़ता है और आर्थिक विकास रफ़्तार पकड़ता है। इस तरह सेल और रेल का एक दूसरे के साथ रेल उत्पादन से जुड़ी गतिविधियों को लेकर रोज का नाता है। सेल ने रेल की बदलती जरूरतों को पूरा करने के लिए उसकी आवश्यकता के अनुसार मात्रा, गुणवत्ता और लंबाई को साल-दर-साल बढ़ाया है। इसके साथ ही सेल ने भारतीय रेलवे द्वारा बताये गए स्पेसिफिकेशन के अनुसार विश्वस्तरीय रेल रोल करने के लिए मानकों में लगातार सुधार किया है। सेल निर्मित रेल देश की एक छोर से दूसरे छोर तक पहुँच बढ़ाती है। महारत्न सेल के भिलाई स्टील प्लांट को रेल स्टील-मेकिंग को पूरा करने के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया है और यहां तक कि यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित सटीक मानक को भी अधिक बेहतर बनाया गया है। सेल और भारतीय रेलवे की देश की बदलती रेल परिवहन की जरूरतों को पूरा करने कि दिशा में रेल उत्पाद और प्रक्रिया को लगातार और बेहतर बनाने के लिए निभाई जा रही साझेदारी 'आत्मनिर्भर भारत' अभियान का अनुकरणीय मिसाल है।

बुधवार से आपकी जिंदगी में बदलने वाला है बहुत कुछ

बैंकिंग से लेकर रसोई तक पड़ेगा असर

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

बुधवार से जुलाई महीना शुरू हो रहा है. 1 जुलाई से जहां एक तरफ सरकार अनलॉक-2 की प्रक्रिया को शुरू कर रही है, वहीं दूसरी तरफ आपके घर की रसोई से लेकर के जेब पर भी कई बातों का असर पड़ेगा. आम आदमी वैसे ही कोरोना और पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों से परेशान हो रहा है, ऐसे में बैंकिंग नियमों और एलपीजी की कीमतों में भी बदलाव होगा। आइये जानते हैं कौन-कौन से प्रमुख बदलाव आपके जीवन में 1 जुलाई से होने वाले हैं....

एटीएम ट्रांजेक्शन पर नहीं मिलेगी छूट

बुधवार से सभी बैंकों के खाताधारकों को एटीएम से कैश ट्रांजेक्शन करने पर किसी तरह की छूट नहीं मिलेगी। पहले की तरह हर महीने केवल मेट्रो शहरों में आठ और नॉन मेट्रो शहरों में 10 ट्रांजेक्शन ही लोग कर सकेंगे. कोरोना वायरस के चलते पहले लोगों को एटीएम से असीमित निकासी की सुविधा दी गई थी।

फिर से खाते में रखना होगा मिनिमम बैलेंस

खाताधारकों को अपने बैंकों के नियमों के हिसाब से हर माह बचत खाते में मिनिमम बैलेंस रखना होगा। मिनिमम मंथली बैलेंस मेंटेन रखने की जरूरत को लॉकडाउन के दौरान खत्म कर दिया था। मेट्रो सिटी, शहरी और ग्रामीण इलाकों में अलग-अलग मिनिमम बैलेंस का चार्ज लगता है।

मिलेगा कम ब्याज

सबसे बड़ी मार ग्राहकों के खाते पर मिलने वाले ब्याज पर पड़ी है। ज्यादातर बैंक बचत खाते में मिलने वाले ब्याज में कमी कर देंगे। जहां पंजाब नेशनल बैंक के खाताधारकों को मिलने वाले ब्याज में 0.50 फीसदी की कमी की जाएगी, वहीं अन्य सरकारी बैंकों में भी अधिकतम 3.25 फीसदी ब्याज मिलेगा.

खाता होगा फ्रीज

इसके साथ ही 1 जुलाई से कई बैंकों में डॉक्यूमेंट जमा नहीं कराने पर लोगों के खाते फ्रीज हो जाएंगे। बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ ही विजया बैंक और देना बैंक में भी ये नियम लागू हो गया है। गौरतलब है कि विजया और देना बैंक का बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय हो चुका है।

बदलेंगी एलपीजी, हवाई ईंधन की कीमतें

तेल मार्केटिंग कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी सिलेंडर और हवाई ईंधन की नई कीमतों की घोषणा करती हैं। पिछले कुछ महीनों से कीमतों में इजाफा हो रहा है। वहीं पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों से उम्मीद लग रही है कि लोगों की रसोई के साथ ही हवाई किराये में लागत काफी बढ़ जाएगी।

अटल पेंशन योजना का बदलेगा नियम

अटल पेंशन योजना में 30 जून के बाद Auto debit फिर शुरू हो सकता है। PFRDA के 11 अप्रैल के सर्कुलर के मुताबिक, कोरोना वायरस महामारी के कारण इस सुविधा को 30 जून तक रोका गया था। इसलिए बैंकों ने अटल पेंशन योजना से ऑटो डेबिट रोक दिया था। 1 जुलाई से यह फिर शुरू हो सकता है।

एमएसएमई का ऑनलाइन पंजीकरण

सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यम (एमएसएमई) 1 जुलाई से ऑनलाइन पंजीकरण करा सकेंगे। सरकार ने इस संदर्भ में बताया था कि यह पंजीकरण स्वघोषित जानकारियों के आधार पर होगा, इसके लिए दस्तावेज अपलोड करने की जरूरत नहीं होगी। मामले से जुडे़ अधिकारी ने बताया कि उद्यमों के पंजीकरण की प्रक्रिया आयकर और जीएसटी के साथ जोड़ी जा रही है। यहां दी गई जानकारियों का सत्यापन पैन नंबर और जीएसटीआईएन के विवरण से किया जाएगा।

कोरोना काल में PF का पैसा निकालने की आखिरी तारीख

केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए लगाए गए लॉकडाउन में पीएफ से पैसा निकालने के लिए नियमों में ढील दी थी। अगर आप अपने पीएफ अकाउंट से कुछ राशि निकालना चाहते हैं तो एक जुलाई से होने जा रहा ये बदलाव महत्वपूर्ण है। एक जुलाई से आप ऐसा नहीं कर पाएंगे. ये सुविधा केवल 30 जून तक थी।

किसान सम्मान निधि में पंजीकरण

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत मोदी सरकार की तरफ से हर साल किसानों को 2000 रुपये की तीन किस्तों में 6000 रुपये दिए जाते हैं। अब तक पांच किस्तें किसानों को भेजी जा चुकी हैं। योजना में 30 जून तक पंजीकरण करा सकते हैं। अगर 30 जून तक वह आवेदन कर देते हैं तो जुलाई में आपको 2000 रुपये मिलेंगे और साथ में अगस्त में भी आपको दूसरी किस्त के रूप में 2000 रुपये और मिल जाएंगे।

म्यूचुअल फंड की खरीद पर लगेगी स्टांप ड्यूटी

एक जुलाई से म्यूचुअल फंड खरीदने पर निवेशकों को उस पर 0.005 फीसदी स्टांप ड्यूटी भी देनी होगी। फिर चाहे आप सिस्टेमेटिक इंवेस्टमेंट प्लान (एसआईपी) और सिस्टेमेटिक ट्रांसफर प्लान (एसटीपी) के जरिए भी म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हो। यह स्टांप ड्यूटी डेट और इक्विटी सभी तरह के म्यूचुअल फंड पर लगेगी. स्टाम्प ड्यूटी लगने का असर सबसे ज्यादा डेट फंड पर देखने को मिलेगा।

कर्ज पुनर्गठन केवल समस्या को टालना

कोविड-19 की वजह से 14 प्रतिशत तक पहुंच सकता है एनपीएः एसएण्डपी

मुंबई। एजेंसी

रिजर्व बैंक कुछ क्षेत्रों के कर्ज का पुनर्गठन करने पर विचार कर रहा है इस तरह की रिपोर्टों के बीच वैश्विक रेटिंग एजेंसी एस एण्ड पी ने मंगलवार को कहा कि कर्ज का पुनर्गठन केवल बैंकों के एनपीए की पहचान को आगे के लिये टालेगा और इससे समस्या का समाधान नहीं होगा।एजेंसी ने कहा है कि महामारी की वजह से आई मंदी और कामकाज में बाधा का बैंकों पर जितना समझा जा रहा था उससके कहीं अधिक गहरा प्रभाव पड़ेगा और बैंकों की सकल गैर- निष्पादित परिसंपत्तियां वित्त वर्ष 2019- 20 के 8.5 प्रतिशत से बढ़कर 14 प्रतिशत तक पहुंच सकती है। एजेंसी का मानना है कि कोविड- 19 महामारी के प्रभाव से भारत के बैंकिग क्षेत्र में जो सुधार आ रहा था वह कई साल पीछे चला जायेगा। इससे रिण प्रवाह पर असर होगा और अंततः अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव पड़ेगा। कोरोना वायरस महामारी के प्रकोप के चलते लॉकडाउन करना पड़ा और आर्थिक गतिविधियां पूरी तरह से बंद हो गई। इसकी वजह से रिजर्व बैंक को बैंकों से कर्ज लिये लोगों को छूट देते हुये छह महीने तक कर्ज की किस्तों को चुकाने से छूट देनी पड़ी। अब एक बार फिर ऐसी रिपोर्टें आ रही है कि रिजर्व बैंक कुछ उपायों के साथ कर्ज के पुनर्गठन की अनुमति देने जा रहा है। एजेंसी ने कहा, " ... पुनर्गठन से संभवतः समस्या का निदान नहीं होगा। यह एनपीए पहचान को केवल आगे के लिये टालेगा, जैसा कि कुछ साल पहले हुआ था।''कोविड-19 महामारी की वजह से कर्ज की वसूली कई साल पीछे चली जायेगी और इसके परिणामस्वरूप बैंकों की फंसी कर्ज की राशि यानी एनपीए में वृद्धि होगी। रेटिंग एजेंसी स्टैण्डर्ड एण्ड पूअर्स की विश्लेषक दीपाली सेठ छाबरिया ने कहा भारतीय बैंकों का एनपीए 13 से 14 प्रतिशत तक पहुंच सकता है जो कि वित्त वर्ष 2019-20 में 8.5 प्रतिशत पर है। ऐसे में बैंकों में फंसे कर्ज की स्थिति का दबाव बढ़ जायेगा। इनके समाधान में भी समय लगेगा। बहरहाल इस स्थिति में 2021-22 में ही एक प्रतिशत तक सुधार आने का अनुमान है।

कोरोना से पहले के स्तर पर पहुंचा डिजिटल पेमेंट, क्रेडिट कार्ड से भुगतान में भी तेजी

मुंबई। आईपीटी नेटवर्क

देश में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई), कार्ड और मोबाइल वॉलेट के जरिए होने वाला डिजिटल पेमेंट ट्रांजेक्शन देश में कोरोना संक्रमण फैलने से पहले के स्तर पर पहुंच गया है। कोरोना के प्रकोप को रोकने के लिए लगाए गए देशव्यापी लॉकडाउन के कारण अप्रैल में इसमें करीब 60 फीसदी की गिरावट आई थी।

आरबीआई के आंकड़ों के मुताबिक नेशनल पेमेंट्स कॉर्प (एनपीसीआई) द्वारा संचालित यूपीआई ने 28 जून तक 2.31 लाख करोड़ रुपये के 1.42 अरब ट्रांजेक्शन प्रोसेस किए। यह इस प्लेटफॉर्म के जरिए एक महीने में सबसे अधिक ट्रांजेक्शन है। इससे पहले अप्रैल में इस चैनल से 1.5 लाख करोड़ रुपये के 99 करोड़ ट्रांजेक्शन प्रोसेस किए गए थे। 2016 में इस प्लेटफॉर्म के शुरू होने के बाद यह सबसे बड़ी मासिक गिरावट थी।

क्या है बढ़ोतरी की वजह

विशेषज्ञों का कहना है कि यूपीआई में बढ़ोतरी की वजह यह है कि ज्यादा से ज्यादा उपभोक्ता कॉन्टैक्टलैस माध्यमों से बिल का भुगतान और खरीदारी कर रहे हैं। गूगल पे में सीनियर डायरेक्टर, प्रॉडक्ट, अंबरीश केंघे ने

कहा, कोविड-19 ने डिजिटल भुगतान की गति बढ़ा दी है। अप्रैल में डिजिटल भुगतान में कमी अब रिकवरी हो चुकी है। उन्होंने कहा कि शुरुआती लॉकडाउन के बाद के महीनों में गूगल पे प्लेटफॉर्म पर बिलों के भुगतान और ऑनलाइन रिचार्ज में 180 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। वॉलमार्ट की पेमेंट कंपनी फोनपे का कहना है कि उसका वॉल्यूम रिकवर हो चुका है। फोनपे के वाइस प्रेजिडेंट स्ट्रैटजी एंड बिजनेस डेवलपमेंट कार्तिक रघुपति ने कहा, जून में पेमेंट वॉल्यूम प्री-लॉकडाउन के स्तर पर आ चुका है। इसकी वजह यह है कि देश के अधिकांश हिस्सों में अब ऑफलाइन और ऑनलाइन कारोबार शुरू हो चुका है।

कार्ड बेस्ड ट्रांजेक्शन में भी तेजी

इसी तरह कार्ड से होने वाला लेनदेन भी प्री-कोविड के स्तर पर पहुंच चुका है। एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा, आरबीएल बैंक और एसबीआई कार्ड्स का कहना है कि उनका कार्ड बेस्ड ट्रांजेक्शन प्री-कोविड वॉल्यूम के 70-80 फीसदी पहुंच चुका है। क्रेडिट कार्ड से भुगतान में ज्यादा तेजी से रिकवरी हुई है जबकि डेबिट कार्ड से भुगतान भी मई की तुलना में जून में बढ़ा है। जानकारों का कहना है कि गैर-जरूरी सामान की आपूर्ति के लिए ई-कॉमर्स कंपनियों को अनुमति और मनोरंजन तथा शिक्षा में डिजिटल शिफ्ट से डिजिटल भुगतान में तेजी आई है। लेकिन एविएशन, फ्यूल, मूवीज और डाइनिंग जैसे सेक्टरों में अभी यह सुस्त है क्योंकि लोग कम सफर कर रहे हैं और सिनेमा हॉल तथा रेस्टोरेंट बंद हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि इन रुझानों से साफ है कि उपभोक्ता धारणा पटरी पर लौट रही है लेकिन फुल रिकवरी में अभी कुछ समय लग सकता है।

जी-20 देशों ने सात महीनों में 59 आयात प्रतिबंधात्मक कदम उठायेः डब्ल्यूटीओ

नयी दिल्ली। एजेंसी

जी-20 देशों ने अक्टूबर 2019 के मध्य से मई 2020 के मध्य तक आयात पाबंदी और कड़ी सीमा शुल्क प्रक्रिया समेत 59 व्यापार प्रतिबंधात्मक कदम उठाये हैं। विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) की एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गयी है। जी-20 सदस्य देशों में भारत, अर्जेन्टीना, आस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, जापान, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका समेत अन्य शामिल हैं। रिपार्ट के अनुसार, "जी-20 देशों ने अक्टूबर 2019 के मध्य से मई 2020 के मध्य तक 154 नये व्यापार और व्यापार संबंधित उपाय किये। इसमें से 95 आयात को सुगम बनाने तथा 59 आयात पर पाबंदी लगाने से जुड़े थे। इन उपायों में 93 (करीब 60 प्रतिशत) कोविड-19 महामारी से जुड़े थे। इसमें कहा गया है कि आलोच्य अवधि में शुल्क में वृद्धि, आयात प्रतिबंध, कड़ी सीमा शुल्क प्रक्रिया, नियार्त शुल्क और अन्य उपाय किये गये। इससे जी-20 देशों का 2.8 प्रतिशत व्यापार प्रभावित हुआ है।

सावन विशेष

शुरुआत और समापन में सावन शुभ लेकिन कावड यात्रा नहीं निकलेगी

6 जुलाई से 3 अगस्त तक श्रद्धालु भगवान शिव का जलाभिषेक करेंगे

✍ डॉ.अशोक शास्त्री

ज्योतिषाचार्य के अनुसार इस बार सावन मास पर अच्छा योग है, लेकिन कोरोना का असर भी रहेगा। सावन सोमवार से शुरू होकर संपन्न भी सोमवार को होने से ज्योतिषाचार्य डॉ अशोक शास्त्री ने इसे शुभ बताया है। मगर कोरोना के चलते सावन में निकलने वाली कावड़ यात्राएं नहीं निकलेगी । दिनांक 6 जुलाई से 3 अगस्त तक सावन रहेगा। जिसमें श्रद्धालु केवल स्थानीय मंदिरों में ही भोले का जलाभिषेक कर सकेंगे।

ज्यातिषाचार्य डॉ. अशोक शास्त्री ने बताया श्रावण प्रतिपदा को सोमवार, उत्तराषाढ़ा, नक्षत्र, वैद्धति योग तथा कोलव नामक करण रहेगा। वहीं चंद्रमा मकर राशि में विचरण करेगा। साथ ही डॉ. शास्त्री के मुताबिक इस वर्ष सावन में ही 36 शुभ योग भी पड रहें हैं , जिससे सावन मास की शुभता और अधिक बढेगी । सावन मास में इस बार 11 सर्वार्थ सिद्धि योग, 10 सिद्धि योग, 12 अमृत योग और तीन अमृत सिद्धि योग रहेंगे ।

मालवा के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य डॉ अशोक शास्त्री ने एक चर्चा के दौरान बताया है कि पहला सोमवार 6 जुलाई को , दूसरा सोमवार 13 जुलाई को , तीसरा सोमवार 20 जुलाई को , चौथा सोमवार 27 जुलाई को और पांचवां व अंतिम सोमवार 3 अगस्त को रहेगा। दूसरी तरफ हर साल शहर से निकलने वाली कावड़ यात्राएं इस साल नहीं निकलेगी। धार से सैंकड़ों कावड़िएं उज्जैन, ओंकारेश्वर सहित विभिन्न शहरों तक पैदल चलकर भोले का जलाभिषेक करते हैं । कोरोना के चलते सरकार ने इस पर कावड़ यात्राओं पर प्रतिबंध लगा दिया है। जिसके चलते इस वर्ष कावड़ यात्रा नहीं निकलेगी।

पांचों सावन सोमवार को विशेष योग बनेंगे, जिनमें रुद्राभिषेक करना श्रेष्ठ रहेगा

पहले सोमवार को शिव के साथ लक्ष्मीनारायण की भी पूजा : 6 जुलाई को उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, वैधृति योग, कौलव करण, प्रतिपदा तिथि रहेगी। यह अभीष्ट फलदायक वन सोमवार रहेगा। मान्यता है कि इस दिन शिव तत्व की साधना और पूजा-अर्चना मंगलकारी, अनिष्ट विनाशक सिद्ध होगी।

दूसरे सोमवार को रुके हुए कार्य सिद्ध होंगे : दूसरा वन सोमवार 13 जुलाई को होगा। इस दिन अष्टमी तिथि होगी, जिसके स्वामी शिव हैं। सोमवार को शिव तिथि का होना विशेष संयोग कारक है। दूसरे वन सोमवार को रेवती नक्षत्र रहेगा, जिसका स्वामी पूषण नामक सूर्य है। समस्त रुके हुए कार्य जल्दी ही संपन्न होंगे।

तीसरे सोमवार को ऋषि-पितृ-गो पूजन भी : सावन का तीसरा सोमवार 20 जुलाई को रहेगा। अमावस्या तिथि रहेगी जो हरियाली अमावस्या के रूप में मनेगी। इस दिन सोमवती अमावस्या विशेष फलदायी रहेगी। ऐसा माना जाता है कि इस दिन ऋषि, पितृ और गौ पूजन करना लाभप्रद रहेगा।

चौथे सोमवार को साध्य योग दिलाएगा प्रतिष्ठा : चौथा सोमवार 27 जुलाई को होगा। सुबह 7:10 बजे तक सप्तमी तिथि रहेगी, इसके बाद अष्टमी तिथि रहेगी। चित्रा नक्षत्र, साध्य योग, वाणिज करण विद्यमान रहेंगे। इस दिन सूर्य और विश्वकर्मा की पूजा विशेष उपयोगी रहेगी। इस पूजा से राजनीतिक उत्थान, उन्नति, यश, मान, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। भूमि-भवन की भी प्राप्ति शीघ्र होगी।

इस बार आएंगे 36 शुभयोग

पांचवें सोमवार को खुलेंगे रोग मुक्ति के द्वार : पांचवां और अंतिम सावन सोमवार तीन अगस्त को रहेगा। इस दिन पूर्णिमा तिथि, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, प्रीति तथा आयुष्मान योग रहेगा। इस दिन शिव पूजा के साथ भगवान सत्यनारायण, विश्व देव तथा ब्राह्मणां की पूजा तथा सम्मान देने से स्वास्थ्य की प्राप्ति होगी। इस दिन जरूरतमंदों को भोजन, वस्त्र, अन्नदान करना चाहिए ।

श्रावण मास के 10 रहस्य

भगवान शिव का माह श्रावण माह प्रारंभ होने वाला है। अषाड़ माह के शुक्ल पक्ष की समाप्ति के पश्चात श्रावण माह का प्रारंभ होता है। अषाड़ माह से ही वर्षा ऋतु का प्रारंभ हो जाता है और इसी माह की शुक्ल एकादशी के दिन देव सो जाते हैं। देवशयनी एकादशी से ही चतुर्मास का प्रारंभ हो जाता है। आओ जानते हैं श्रावण माह के 10 रहस्य।

1. सत्संग का महत्व : श्रावण शब्द श्रवण से बना है जिसका अर्थ है सुनना। अर्थात सुनकर धर्म को समझना। इस माह में सत्संग का महत्व है। इस माह में पतझड़ से मुरझाई हुई प्रकृति पुनर्जन्म लेती है।

2. व्रतों का प्रारंभ : श्रावण माह से व्रत और साधना के चार माह अर्थात चातुर्मास प्रारंभ होते हैं। ये 4 माह हैं- श्रावण, भाद्रपद, आश्?विन और कार्तिक। पौराणिक कथा के अनुसार देवी सती ने अपने दूसरे जन्म में शिव को प्राप्त करने हेतु युवावस्था में श्रावण महीने में निराहार रहकर कठोर व्रत किया और उन्हें प्रसन्न कर विवाह किया था। इसलिए यह माह विशेष है।

3. संपूर्ण माह व्रत रखते हैं : श्रावण माह में सिर्फ सावन सोमवार ही नहीं संपूर्ण माह ही व्रत रखना जाता है। जिस तरह गुड फ्राइडे के पहले ईसाइयों में 40 दिन के उपवास चलते हैं और जिस तरह इस्लाम में रमजान माह में रोजे (उपवास) रखे जाते हैं उसी तरह हिन्दू धर्म में श्रावण मास को पवित्र और व्रत रखने वाला माह माना गया है। पूरे श्रावण माह में निराहारी या फलाहारी रहने की हिदायत दी गई है। इस माह में शास्त्र अनुसार ही व्रतों का पालन करना चाहिए। मन से या मनमानों व्रतों से दूर रहना चाहिए। संपूर्ण माह नहीं रख सकते हैं तो सोमवार सहित कुछ खास दिनों व्रत का पालन अवश्य करें।

4. व्रत का नियम : श्रावण माह में दूध, शकर, दही, तेल, बैंगन, पत्तेदार सब्जियां, नमकीन या मसालेदार भोजन, मिठाई, सुपारी, मांस और मदिरा का सेवन नहीं किया जाता। इस दौरान बाल और नाखुन नहीं काटना चाहिए। श्रावण माह में यात्रा, सहवास, वार्ता, भोजन आदि त्यागकर नियमपूर्वक व्रत रखना चाहिए तो ही उसका फल मिलता है। दिन में फलाहार लेना और रात को सिर्फ पानी पीना चाहिए।

जिसकी शारीरिक स्थिति ठीक न हो व्रत करने से उत्तेजना बढ़े और व्रत रखने पर व्रत भंग होने की संभावना हो उसे व्रत नहीं करना चाहिए। रजस्वरा स्त्री, जरूरी यात्रा या युद्ध के हालात में भी व्रत नहीं रखना चाहिए इस व्रत को रखने के तीन कारण है पहला दैहिक, दूसरा मानसिक और तीसरा आत्मिक रूप से शुद्ध होकर पुर्नजीवन प्राप्त करना और आध्यात्मिक रूप से मजबूत होना। इससे काया निरोगी हो जाती है।

5. उपाकर्म करना : श्रावण माह में श्रावणी उपाकर्म करने का महत्व भी है। यह कर्म किसी आश्रम, जंगल या नदी के किनारे किसी संन्यासी की तरह रहकर संपूर्ण किया जाता है। श्रावणी उपाकर्म के 3 पक्ष हैं- प्रायश्चित संकल्प, संस्कार और स्वाध्याय। पूरे माह किसी नदी के किनारे किसी गुरु के सान्निध्य में रहकर श्रावणी उपाकर्म करना चाहिए।

6. इस माह के व्रत-त्योहार : इस माह में सोमवार, गणेश चतुर्थी, मंगला गौरी व्रत, मौना पंचमी, कामिका एकादशी, ऋषि पंचमी, 12वीं को हिंडोला व्रत, हरियाली अमावस्या, विनायक चतुर्थी, नाग पंचमी, पुत्रदा एकादशी, त्रयोदशी, वरा लक्ष्मी व्रत, नराली पूर्णिमा, श्रावणी पूर्णिमा, शिव चतुर्दशी और रक्षा बंधन आदि पवित्र दिन आते हैं।

7. तीन तरह के व्रत : पुराणों और शास्त्रों के अनुसार सोमवार के व्रत 3 तरह के होते हैं- सावन सोमवार, सोलह सोमवार और सोम प्रदोष। हालांकि महिलाओं के लिए सावन सोमवार की व्रत विधि का उल्लेख मिलता है। उन्हें उस विधि के अनुसार ही व्रत रखने की छूट है।

शिवपुराण के अनुसार जिस कामना से कोई इस मास के सोमवारों का व्रत करता है, उसकी वह कामना अवश्य एवं अतिशीघ्र पूरी हो जाती है। जिन्हें 16 सोमवार व्रत करने हैं, वे भी सावन के पहले सोमवार से व्रत करने की शुरुआत कर सकते हैं। इस मास में भगवान शिव की बेलपत्र से पूजा करना श्रेष्ठ एवं शुभ फलदायक है।

8. यदि संपूर्ण माह व्रत रखें तो क्या करना चाहिए?

पूर्ण श्रावण कर रहे हैं तो इस दौरान फर्श पर सोना और सूर्योदय से पहले उठना बहुत शुभ माना जाता है। उठने के बाद अच्छे से स्नान करना और अधिकतर समय मौन रहना चाहिए। दिन में फलाहार लेना और रात को सिर्फ पानी पीना। इस व्रत में दूध, शकर, दही, तेल, बैंगन, पत्तेदार सब्जियां, नमकीन या मसालेदार भोजन, मिठाई, सुपारी, मांस और मदिरा का सेवन नहीं किया जाता। श्रावण में पत्तेदार सब्जियां यथा पालक, साग इत्यादि का त्याग कर दिया जाता है। इस दौरान दाढ़ी नहीं बनाना चाहिए, बाल और नाखुन भी नहीं काटना चाहिए। इष्टदेव के मंत्रों का मौन जप करना चाहिए, उनका ध्यान करना चाहिए उनकी कथाएं सुननी चाहिए और उनकी पूजा करनी चाहिए।

9. इस तरह के व्रत रखना वर्जित : अधिकतर लोग दो समय खूब फरियाली खाकर उपवास करते हैं। कुछ लोग एक समय ही भोजन करते हैं। कुछ लोग तो अपने मन से ही नियम बना लेते हैं और फिर उपवास करते हैं। यह भी देखा गया है कुछ लोग चप्पल छोड़ देते हैं लेकिन गाली देना नहीं। जबकि व्रत में यात्रा, सहवास, वार्ता, भोजन आदि त्यागकर नियमपूर्वक व्रत रखना चाहिए तो ही उसका फल मिलता है। हालांकि उपवास में कई लोग साबूदाने की खिचड़ी, फलाहार या राजगिरे की रोटी और भिंडी की सब्जी खूब ठूसकर खा लेते हैं। इस तरह के उपवास से कैसे लाभ मिलेगा? उपवास या व्रत के शास्त्रों में उल्लेखित नियम का पालन करेंगे तभी तो लाभ मिलेगा।

शिव के जलाभिषेक का फल

श्रावण मास को मासोत्तम मास कहा जाता है। श्रवण नक्षत्र तथा सोमवार से भगवान शिव शंकर का गहरा संबंध है। इसी माह में भगवान शिव और प्रकृति अनेक लीलाएं रचते हैं। कहते हैं कि जब समुद्र मंथन से निकले हलाहल विष को भगवान शंकर ने पीकर उसे कंठ में अवरुद्ध कर दिया तो उस तपन को शांत करने के लिए देवताओं ने उनका जलाभिषेक इसी माह में किया था। इसीलिए इस माह में शिवलिंग या ज्योतिर्लिंगों का दर्शन एवं जलाभिषेक करने से अश्वमेघ यज्ञ के समान फल प्राप्त करता है तथा शिवलोक को पाता है।

कोरोना काल में मारुति ने बेची 57,428 गाड़ियां, हुंडई की बिक्री भी बढ़ी

नई दिल्ली। एजेंसी

देश की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया (Maruti Suzuki) ने जून के बिक्री के आंकड़े जारी किए हैं। मई में कंपनी ने 18,539 गाड़ियां बेची थी जबकि जून में उसकी बिक्री 57,428 यूनिट रही। हालांकि, पिछले साल यानी 2019 जून में मारुति ने 1,24,708 कारें बेची थी। इस तरह पिछले साल के मुकाबले कंपनी की बिक्री में 54 फीसदी की गिरावट आई है। कोरोना वायरस लॉकडाउन की वजह से देश में मारुति के सभी शोरूम बंद थे, इसीलिए मई में उसकी बिक्री में गिरावट आई थी। लेकिन अनलॉक-1 में मिली छूटी के बाद वाहनों की बिक्री में तेजी आई है।कंपनी की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक, जून में कुल बिक्री 57,428 यूनिट रही। कंपनी की घरेलू बिक्री 53,139 यूनिट रही जबकि उसके 4,289 गाड़ियों का निर्यात किया। जून तिमाही में कंपनी कुल 76599 वाहन बेचे। इनमें उसकी घरेलू बिक्री 66165 यूनिट रही। कंपनी ने कहा कि जून 2020 के दौरान उसकी बिक्री के आंकड़ों को कोविड-19 महामारी, लॉकडाउन और सुरक्षा प्रतिबंधों के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। कंपनी का कहना है कि वह वैल्यू चेन के सभी सदस्यों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के प्रति कटिबद्ध है। सभी प्लांट में उत्पादन बढ़ाया जा रहा है लेकिन साथ ही नियमों का पूरा ध्यान रखा जा रहा है।

पिछले साल के मुकाबले घटी बिक्री

कंपनी ने बयाया कि उसने जून में 4,289 इकाइयों का निर्यात किया जो पिछले साल के समान महीने के मुकाबले 56.4 प्रतिशत कम है। इस दौरान ऑल्टो और वैगनआर जैसी छोटी कारों की बिक्री 10,458 यूनिट्स रही, जो 44.2 फीसदी कमी को दर्शाता है। इसी तरह स्विफ्ट, सेलेरियो, इग्निस, बलेनो और डिजायर जैसे मॉडलों वाले कॉम्पैक्ट खंड में बिक्री 57.6 प्रतिशत घटकर 26,696 इकाई रही। मझोले आकार की सेडान सियाज की बिक्री पिछले महीने 553 इकाई रही, जबकि सालभर पहले की समान अवधि में यह 2,322 इकाई थी।

हुंडई ने बेची 26820 गाड़ियां

हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड ने भी जून में 26820 गाड़ियां बेची। कंपनी ने एक बयान में कहा कि उसकी सभी नई-पुरानी गाड़ियों को अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। कंपनी ने जून में घरेलू बाजार में 21320 वाहन बेचे। साथ ही 5500 गाड़ियां विभिन्न देशों को निर्यात कीं। कंपनी ने कहा कि वह भारत सरकार की मेक इन इंडिया पहल के लिए समर्पित है।

सस्ता सोना भूल जाइए टूट गए सारे रिकॉर्ड

नई दिल्ली। एजेंसी

जुलाई के पहले ही दिन सोने की कीमतों ने एक और इतिहास रच दिया। एक जुलाई यानी बुधवार को 24 कैरेट सोने का हाजिर भाव अब तक के सर्वोच्च शिखर पर पहुंच गया है। देशभर के सर्राफा बाजारों बुधवार सुबह सोना 421 रुपये उछल कर 48980 रुपये प्रति 10 ग्राम के रेट से बिका। इससे पहले जून माह में सोने ने तीन नए रिकॉर्ड बनाए और एक के बाद एक ये सारे रिकॉर्ड ध्वस्त होते गए। वहीं आज चांदी की कीमतों में 1116 रुपये प्रति किलोग्राम का उछाल आया है। अब चांदी 49716 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। बता दें सोमावार को 24 कैरेट सोना 48600 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया था। वहीं मंगलवार को मामूली परिवर्तन हुआ और आज सोने के रेट ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट (ibjarates.com) सोने-चांदी की औसत कीमत अपटेड करती है। ibjarates के मुताबिक एक जुलाई 2020 को सोने-चांदी के रेट इस प्रकार रहे...

वहीं 23 कैरेट सोने का भाव भी 419 रुपये चढ़कर 48784 रुपये प्रति दस ग्राम पर पहुंच गया है। जबकि 22 कैरेट सोने का मूल्य अब 386 रुपये महंगा होकर 44866 और 18 कैरेट का रेट 36735 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया है। इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन दिल्ली के मीडिया प्रभारी राजेश खोसला के मुताबिक र्रि देशभर के 14 सेंटरों से सोने-चांदी का करेंट रेट लेकर इसका औसत मूल्य बताता है। खोसला कहते हैं कि सोने-चांदी का करेंट रेट या यूं कहें हाजिर भाव अलग-अलग जगहों पर अलग हो सकते हैं पर इनकी कीमतों में मामूली अंतर होता है।

हाजिर मांग और वैश्विक संकेतों से चांदी वायदा कीमतों में तेजी

मजबूत हाजिर मांग और वैश्विक संकेतों के कारण वायदा कारोबार में बुधवार को चांदी की कीमत 98 रुपये की तेजी के साथ 49,749 रुपये प्रति किग्रा हो गई। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में चांदी के जुलाई महीने में डिलीवरी वाले अनुबंध की कीमत 98 रुपये अथवा 0.2 प्रतिशत की तेजी के साथ 49,749 रुपये प्रति किग्रा हो गयी जिसमें 702 लॉट के लिए कारोबार हुआ। बाजार विश्लेष्कों ने कहा कि घरेलू बाजार में तेजी के रुख के कारण कारोबारियों की ताजा लिवाली बढ़ने से चांदी वायदा कीमतों में तेजी आई। वैश्विक स्तर पर, न्यूयॉर्क में, चांदी की कीमत 0.74 प्रतिशत की तेजी के साथ 18.77 डॉलर प्रति औंस हो गई।

यह है सोने के दाम बढ़ने की बड़ी वजह

एंजेल ब्रोकिंग के डिप्टी वाइस प्रेजिडेंट (कमोडिटी एंड करेंसी) अनूज गुप्ता का कहना है कि आईएमएफ ने वर्ष 2020 के लिए वैश्विक अर्थव्यवस्था के अनुमान को घटाकर 4.9 फीसदी कर दिया है, इससे बाजार की धारणा कमजोर हुई है। साथ ही अर्थव्यवस्था में अनिश्चितता और रोजगार के मोर्चे पर बढ़ती आशंका से भी लोग निवेश के लिए ज्वेलरी की बजाय म्यूचुअल फंड के जरिये सोने में निवेश (ई-गोल्ड) को ज्यादा तरजीह दे रहे हैं। विशेषज्ञों की मानें तो कोरोना संकट के बीच जारी वैश्विक अनियचितता के चलते सोने में तेजी का दौर जारी रह सकता है। सोने के दाम में तेजी पिछले एक दशक से जारी है।

कोविड-19 पर नियंत्रण के बाद अर्थव्यवस्था की स्थिति सुधरेगी : नीति आयोग

नयी दिल्ली। एजेंसी

नीति आयोग का कहना है कि कोविड-19 महामारी पर नियंत्रण के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार आएगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने मंगलवार को 'स्वच्छ ऊर्जा अर्थव्यवस्था की ओरः कोविड-19 के बाद भारत के ऊर्जा और मोबिलिटी क्षेत्र में अवसर' विषय पर रिपोर्ट पेश किए जाने के मौके पर कहा कि इस समय जो देश में जो सुधार हो रहे हैं, उनकी वजह से आगे चलकर भारत की वृद्धि दर अपने समकक्ष देशों से अधिक रहेगी।कुमार ने कहा कि इस महामारी पर नियंत्रण के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति सुधरने लगेगी। अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष (आईएमएफ) ने पिछले सप्ताह अनुमान लगाया है कि 2020 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 4.5 प्रतिशत की गिरावट आएगी। आईएमएफ ने कहा है कि कोरोना वायरस की वजह से भारत में आर्थिक गतिविधियां बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। हालांकि, इसके साथ ही आईएमएफ ने कहा कि 2021 में भारतीय अर्थव्यवस्था छह प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करेगी। कुमार ने कहा कि भारत के मजबूत लोकतांत्रिक संस्थान नीतिगत स्थिरता को आगे बढ़ाते हैं। यदि इनका क्रियान्वयन बेहतर तरीके से होता है तो वृद्धि दर में भारत अपने समकक्षों से आगे रहेगा। इसी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) अमिताभ कान्त ने कहा कि स्वच्छ ऊर्जा भारत के आर्थिक पुनरोद्धार और अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में प्रमुख भूमिका निभाएगी। उन्होंने कहा कि हमें अपने घरेलू नवोन्मेषी पारिस्थितिकी तंत्र का दोहन करना होगा ताकि नए सामान्य में देश और उद्योग के लिए मूल्य प्राप्त किया जा सके। रिपोर्ट में कहा गया है कि कोविड-19 की वजह से देश के इलेक्ट्रिक वाहन बाजार में बदलाव आ सकता है क्योंकि लोग उचित मूल्य के उत्पादों की मांग करेंगे और इसके चलते विनिर्माता परंपरागत वाहनों का उत्पादन शुरू करेंगे। रिपोर्ट में कहा गया है कि इलेक्ट्रिक वाहनों के उत्पादन में विलंब हो सकता है, क्योंकि विनिर्माता मांग पैदा करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे और भारत चरण-छह उत्सर्जन मानकों वाले वाहनों का उत्पादन करेंगे। इसके अलावा चीन से कलपुर्जों के आयात पर अंकुशों से इलेक्ट्रिक वाहनों का विनिर्माण प्रभावित हो सकता है।

बढ़ती मांग के कारण रिफाइंड सोया वायदा कीमतों में तेजी

नयी दिल्ली। एजेंसी

सोय तेल में सटोरियों द्वारा अपने सौदों के आकार बढ़ाने के कारण वायदा कारोबार में बुधवार को रिफाइंड सोयातेल की कीमत 6.9 रुपये की तेजी के साथ 806 रुपये प्रति 10 किग्रा हो गयी। एनसीडीईएक्स में रिफाइंड सोयातेल के जुलाई महीने में डिलीवरी वाले अनुबंध की कीमत 6.9 रुपये अथवा 0.86 प्रतिशत की तेजी के साथ 806 रुपये प्रति 10 किग्रा हो गयी जिसमें 23,465 लॉट के लिए कारोबार हुआ। रिफाइंड सोयातेल के अगस्त महीने में डिलीवरी वाले अनुबंध की कीमत 7.1 रुपये अथवा 0.9 प्रतिशत की तेजी के साथ 799 रुपये प्रति 10 किग्रा हो गयी जिसमें 16,435 लॉट के लिए कारोबार हुआ। बाजार विश्लेषकों ने कहा कि कारोबारियों द्वारा अपने सौदों का आकार बढ़ाने के कारण मुख्यतः यहां वायदा कारोबार में रिफाइंड सोयातेल कीमतों में तेजी आई।

वाहन दुर्घटना पीड़ितों को 2.5 लाख रुपये तक नकद रहित इलाज की सुविधा देगी सरकार

नयी दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

सरकार ने बुधवार को कहा कि उसने सड़क दुर्घटना पीड़ितों को नकद रहित (कैशलेस) इलाज की सुविधा उपलब्ध कराने को लेकर रूपरेखा तैयार कर लिया है।राज्यों के परिवहन सचिवों और आयुक्तों को भेजे पत्र के अनुसार योजना के तहत बीमा कवर 2.5 लाख रुपये प्रति मामला होगा। देश में हर साल करीब 5 लाख सड़क हादसे होते हैं जिसमें करीब 1.5 लाख लोगों की मौत होती है जबकि करीब 3 लाख अपाहिज हो जाते हैं या उन्हें गंभीर चोटें लगती हैं। इस लिहाज से यह योजना खासा महत्वपूर्ण है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने एक बयान में कहा, "मंत्रालय ने मोटर दुर्घटना पीड़ितों का कैशलेस उपचार आरंभ करने की योजना को कार्यान्वित करने के लिए एक खाका तैयार किया है... इसमें बेहद महत्वपूर्ण समय के दौरान पीड़ितों का उपचार शामिल है।" इस बारे में मोटर वाहन अधिनियम 2019 में भी इस पर विचार किया गया है। बयान के अनुसार मंत्रालय ने सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में प्रधान सचिवों तथा परिवहन सचिवों को पत्र लिखकर उनसे इस महीने की 10 तारीख तक योजना की संकल्पना नोट पर उनके विचार मांगा है। इस योजना में मोटर वाहन दुर्घटना फंड का सृजन भी शामिल है। इसमें कह गया है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण पीएम-जेएवाई (प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना) की नोडल एजेंसी है तथा 21,000 अस्पतालों के साथ देश भर में इसकी उपस्थिति है। इसके कारण प्राधिकरण को इस योजना को कार्यान्वित करने का जिम्मा सौंपा गया है।मंत्रालय ने कहा कि इस योजना में देश में सड़क उपयोग करने वाले सभी उपयोगकर्ताओं को अनिवार्य रूप से बीमा कवर उपलब्ध कराने का विचार है। कोष का उपयोग सड़क दुर्घटना के पीड़ितों के उपचार के लिए एवं दुर्घटना में जान गवां चुके व्यक्तियों के परिवारजनों या घायलों की क्षतिपूर्ति के भुगतान के लिए किया जाएगा।

ताजा सौदों की लिवाली से ग्वारसीड वायदा कीमतों में तेजी

नयी दिल्ली। एजेंसी

हाजिर बाजार में मजबूती के रुख के कारण सटोरियों ने अपने सौदों के आकार को बढ़ाया जिससे बुधवार को ग्वारसीड की कीमत 11 रुपये की तेजी के साथ 3,627 रुपये प्रति 10 क्विन्टल हो गयी। एनसीडीईएक्स में ग्वारसीड के जुलाई महीने में डिलीवरी वाले अनुबंध की कीमत 11 रुपये अथवा 0.3 प्रतिशत की तेजी के साथ 3,627 रुपये प्रति 10 क्विन्टल हो गयी जिसमें 23,245 लॉट के लिए कारोबार हुआ। ग्वारसीड के अगस्त महीने में डिलीवरी वाले अनुबंध की कीमत 12 रुपये अथवा 0.33 प्रतिशत की तेजी के साथ 3,608 रुपये प्रति 10 क्विन्टल हो गयी जिसमें 19,355 लॉट के लिए कारोबार हुआ। बाजार सूत्रों ने कहा कि उत्पादक क्षेत्रों से मामूली आपूर्ति के कारण हाजिर बाजार में मजबूती के रुख को देखते हुए सटोरियों ने अपने सौदों के अकार को बढ़ाया जिससे यहां वायदा कारोबार में ग्वारसीड कीमतों में तेजी आई।

चीनी कंपनियों को एक और झटका

बीएसएनएल-एमटीएनएल की 4 जी सेवाओं को अपग्रेड करने का टेंडर रद्द

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

दूरसंचार विभाग ने 59 चीनी मोबाइल ऐप को डिलीट करने के दो दिन बाद बुधवार को दूरसंचार विभाग की बीएसएनएल और एमटीएनएल की 4 जी सेवाओं को अपग्रेड करने के लिए निविदा रद्द कर दी। सूत्रों के मुताबिक ऐसा चीनी कंपनियों को झअका देने के लिए किया गया है। केंद्र सरकार ने बीएसएनएल को निर्देश दिया था कि वह अपग्रेड के लिए चीनी उपकरण का इस्तेमाल न करे, जिसकी लागत 7,000-8,000 करोड़ रुपये है। नई प्रक्रिया से चीनी कंपनियों के अयोग्य होने की संभावना बढ़ गई है। अदऊ भारत में निर्मित उपकरणों के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए निजी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के साथ परामर्श कर रहा है।

दूरसंचार नियमन के सलाहकार महेश उप्पल ने कहा, भारत मोबाइल फोन का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक हो सकता है, लेकिन 75% Internal Components चीन से आते हैं, जिससे अचानक स्विच करना मुश्किल हो जाएगा।' उप्पल ने कहा, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में पांच प्रमुख खिलाड़ी दो चीनी कंपनियों के साथ एरिक्सन, नोकिया, सैमसंग, हुआवेई और जेडटीई हैं। अदऊ अधिकारियों के अनुसार, 5G स्पेक्ट्रम ट्रायल जो अभी भी प्रस्ताव के चरण में है प्लैंग इसमें भाग लेने वाला था।

बता दें सरकार ने सोमवार को राष्ट्रीय सुरक्षा मद्देनजर 59 चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया। आईटी मंत्रालय ने सोमवार को जारी एक आधिकारिक बयान में कहा कि उसे विभिन्न स्रोतों से कई शिकायतें मिली हैं, जिनमें एंड्रॉइड और आईओएस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कुछ मोबाइल ऐप के दुरुपयोग के बारे में कई रिपोर्ट शामिल हैं। इन रिपोर्ट में कहा गया है कि ये एप उपयोगकर्ताओं के डेटा को चुराकर, उन्हें गुपचुक तरीके से भारत के बाहर स्थित सर्वर को भेजते हैं।

बैन लिस्ट में ये ऐप भी शामिल

प्रतिबंधित सूची में वीचैट , बीगो लाइव ,हैलो, लाइकी, कैम स्कैनर, वीगो वीडियो, एमआई वीडियो कॉल - शाओमी, एमआई कम्युनिटी, क्लैश ऑफ किंग्स के साथ ही ई-कॉमर्स प्लेटफार्म क्लब फैक्टरी और शीइन शामिल हैं।

महाराष्ट्र सरकार भी चीनी प्रोजेक्ट्स को लेकर ले चुकी है बड़ा फैसला

पिछले दिनों महाराष्ट्र सरकार ने भी चीनी प्रोजेक्ट्स को लेकर एक बड़ा फैसला लिया। महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार ने चीन की तीन कंपनियों के साथ हुए करार पर रोक लगा दी। बताया जा रहा है कि मैग्नेटिक महाराष्ट्र 2.0 समिट में राज्य सरकार ने तीन चीनी कंपनियों के साथ पांच हजार करोड़ के निवेश के प्रोजेक्ट पर साइन किए थे। महाराष्ट्र के उद्योग मंत्री सुभाष देसाई ने कहा कि हमने यह फैसला केंद्र सरकार के परामर्श से लिया है। उन्होंने बताया कि भारत-चीन सीमा पर 20 भारतीय सैनिकों की हत्या से पहले इन समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए थे। उन्होंने बताया कि विदेश मंत्रालय ने चीनी कंपनियों के साथ किसी भी अन्य समझौते पर हस्ताक्षर न करने की राज्य सरकार को सलाह दी है। उन्होंने बताया कि मैग्नेटिक महाराष्ट्र 2.0 समिट में राज्य सरकार ने दुनियाभर की कंपनियों से 16000 करोड़ रुपये से अधिक के समझौतों पर हस्ताक्षर किए थे जिनमें चीनी कंपनियां भी शामिल थीं।

इसमें पुणे में तालेगांव में ऑटोमोबाइल विनिर्माण इकाई स्थापित करने के लिए चीन की ग्रेट वॉल मोटर्स के साथ 3,770 करोड़ रुपये का एमओयू साइन किया था। इसमें चीन की फोटॉन और पीएमआई इलेक्ट्रो मोबिलिटी के बीच 1,000 करोड़ रुपये की साझेदारी शामिल है। इसके अलावा, हेंग्लू इंजीनियरिंग ने पुणे में अपनी इकाई फेज छ्ष में विस्तार की योजनाओं के लिए 250 करोड़ रुपये की प्रतिबद्धता जताई थी।चीन के अलावा अमेरिका, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर और कई बड़ी कंपनियों ने नौ अन्य समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए थे।

दिल्ली-मेरठ रैपिड रेल के लिए चीनी कंपनी को अभी नहीं मिला है टेंडर

बता दें भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा पर हुई झड़प के बाद दिल्ली-मुंबई हाईवे को लेकर काफी चर्चा होने लगी। कहा गया कि इस प्रस्तावित रेल रूट पर 5.6 किलोमीटर लंबे अंडरग्राउंड हिस्से को बनाने के लिए चीन की कंपनी को टेंडर दिया गया है। सोशल मीडिया में इसके खिलाफ आवाज उठने लगी। इसके बाद केंद्र सरकार ने स्थिति साफ करते हुए कहा कि अभी तक इस काम को लेकर टेंडर फाइनल नहीं किया गया है।

केंद्र सरकार द्वारा जारी बयान में कहा गया, 'यह स्पष्ट है कि इसका निर्माण एडीबी के फंड से होगा। इसके तहत टीबीएम और एक आरआरटीएस स्टेशन से गुजरने वाले 5.6 किमी लंबे सुरंग के डिजाइन और निर्माण का काम होगा। पिछले साल नौ नवंबर को इसके लिए टेंडर मांगे गए थे, जिसे तकनीक रूप से 16 मार्च को खोला गया।' इस प्रोजेक्ट के लिए पांच कंपनी ने टेंडर दिया। उनमें SKEC (कोरिया) और Tata, STEC (चीन), L&T (भारत), Afcons (भारत) और GulermakAgir (तुर्की) शामिल हैं। STEC (चीन) ने सबसे सस्ता टेंडर दिया है। केंद्र सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया कि अभी तक टेंडर को फाइनल नहीं किया गया है। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि एडीबी या विश्व बैंक या बहु-पार्श्व खरीद दिशानिर्देश फर्म या देश के बीच भेदभाव की अनुमति नहीं देते हैं।

कृषि क्षेत्र में निजी निवेश, आधुनिक प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल को बढ़ाने का आह्वान

नयी दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मंगलवार को किसानों की आय बढ़ाने के लिए कृषि क्षेत्र में निजी निवेश बढ़ाने और इस क्षेत्र में आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किये जाने की बात पर जोर दिया। नयी दिल्ली प्रबंधन संस्थान (एनडीआईएम) के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि खेती के काम को न केवल लाभप्रद बनाकर बल्कि आकर्षक बनाते हुए कृषि क्षेत्र में शिक्षित लोगों को आकर्षित करने की भी आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि सरकार ने कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न सुधारों की घोषणा की है जैसे ठेका खेती को बढ़ावा देना, आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन और थोक बाजारों से बाहर व्यापार करने की अनुमति आदि उपाय शामिल हैं। तोमर ने कहा, ''हमारे देश में कृषि एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है। हमारा लगभग 60 प्रतिशत कार्यबल कृषि क्षेत्र पर निर्भर है।'' हालांकि, उन्होंने इस बात पर अफसोस जताया कि कृषि क्षेत्र में निजी क्षेत्र का निवेश स्तर काफी कम है और आधुनिक तकनीकों की उपलब्धता भी कम है। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि कृषि क्षेत्र में अधिक निजी निवेश हो और आधुनिक तकनीक का उपयोग बढ़े। तोमर ने देश में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और खाद्यान्न उत्पादन में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए किसानों की सराहना की।

सभी एप को देश के डेटा प्रमाणिकता, निजता नियमों का पालन करना चाहिए : नीति आयोग

नयी दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने मंगलवार को कहा कि भारत में सेवाएं देने वाली सभी मोबाइल एप को देश के डेटा सुरक्षा, प्रमाणिकता और निजता नियमों का पालन करना चाहिए। उनका यह बयान सरकार के चीन की 59 एप पर प्रतिबंध लगाने के एक दिन बाद आया है।देश को डेटा के मामले में संप्रभु होने की बात से सहमति जताते हुए कांत ने कहा कि एप को उनके मूल देश और डेटा की अंतिम पहुंच को लेकर पारदर्शी रवैया अपनाना चाहिए। सरकार ने 59 चीनी एप पर प्रतिबंध उनके देश की सुरक्षा, अखंडता और सुरक्षा के लिए हानिकारक होने के आधार पर लगाया है। कांत ने कहा, ''देश में काम करने वाली सभी एप को भारत के डेटा प्रमाणिकता, निजता, संप्रभुता और पारदर्शिता नियमों का पालन करना चाहिए।'' उन्होंने ट्वीट किया, '' उन्हें (एप को) डाटा के उद्गम और उसके अंतिम पड़ाव के बारे में पारदर्शी होना चाहिए। भारत को डेटा के मामले में संप्रभु देश होना चाहिए। यह महत्वपूर्ण है। जिन एप के खिलाफ कार्रवाई की गयी है, वे जीवनशैली से जुड़े एप हैं।'' कई ट्वीट की श्रृंखला में उन्होंने कहा कि भारतीय प्रौद्योगिकी कंपनियों के लिए यह सबसे सही समय है कि वे देश-दुनिया के लिए प्रौद्योगिकी समाधान विकसित करें। उन्होंने 'आरोग्य सेतु' एप का उदाहरण देते हुए कहा कि यह देश के लिए देश में बना प्रौद्योगिकी नवोन्मेष का अनूठा उदाहरण है। इसका उपयोग लाखों भारतीय कर रहे हैं। आरोग्य सेतु एप को कोरोना-19 महामारी के दौरान लोगों के संपर्कों पर निगरानी के लिए विकसित किया गया है। लद्दाख में गलवान घाटी में भारत और चीन में तनाव के बीच सरकार ने सोमवार को 59 चीनी एप पर प्रतिबंध लगा दिया। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इस मामलें में कार्रवाई करते हुए कहा के इन एप के खिलाफ शिकायतें मिल रही थीं कि ये भारत के डाटा को गुपचुप तरीके से विदेश के सर्वर में पहुंचाते थे। सरकार ने इन एप की इस तरह की गतिविधियों को देश की संप्रभुता और अखंडता के खिलाफ माना है।

आयातक एवं निर्यातक ऑनलाइन ले सकेंगे आइईसी

लुधियाना। एजेंसी

डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड (डीजीएफटी) ने आयातकों एवं निर्यातकों के लिए अपनी सेवाओं को सौ फीसद ऑनलाइन करने के लिए कदम उठाए हैं। इसके लिए इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड (आइईसी) को ऑनलाइन प्रोसेस कर दिया है। यानि आइईसी नया लेने, पुराने में बदलाव करने एवं दस्तावेज जमा कराने की सारी प्रक्रिया उद्यमी अपने ई-मेल, मोबाइल नंबर एवं डिजिटल-कीज के माध्यम से कर सकेंगे। यह सुविधा 13 जुलाई से काम करना शुरू कर देगी। दूसरे चरण में डीजीएफटी की तमाम सेवाएं मसलन एडवांस ऑथराइजेशन, एक्सपोर्ट प्रोमोशन कैपिटल गुड्स (ईपीसीजी) को भी ऑनलाइन कर दिया जाएगा। ज्वाइंट डीजीएफटी सुविध शाह का कहना है कि पैन धारक भारत का कोई भी नागरिक एवं व्यवसायिक संस्थान आइईसी हासिल कर सकता है। किसी भी तरह के आयात एवं निर्यात के लिए आइईसी आवश्यक होता है। इस प्रक्रिया को ऑन लाइन करने से आयातकों एवं निर्यातकों को काफी लाभ होगा। उनका वक्त बचेगा और वे आसानी से आइईसी हासिल कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि डीजीएफटी ट्रेड को बेहतर सेवाएं देने के लिए तत्पर है।

स्वामी/मुद्रक/प्रकाशक सचिन बंसल द्वारा अपनी दुनिया प्रिंटर्स, 13, प्रेस काम्पलेक्स, ए.बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 18, सेक्टर-डी-2, सांवेर रोड, इंडस्ट्रीयल एरिया, जिला इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित । संपादक- सचिन बंसल

सूचना/चेतावनी- इंडियन प्लास्ट टाइम्स अखबार के पूरे या किसी भी भाग का उपयोग, पुनः प्रकाशन, या व्यावसायिक उपयोग बिना संपादक की अनुमति के करना वर्जित है। अखबार में छपे लेख या विज्ञापन का उद्देश्य सूचना और प्रस्तुतिकरण मात्र है। अखबार किसी भी प्रकार के लेख या विज्ञापन से किसी भी संस्थान की सिफारिश या समर्थन नहीं करता है। पाठक किसी भी व्यावसायिक गतिविधि के लिए स्वविवेक से निर्णय करें। किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र इंदौर, मप्र रहेगा।